

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जू 6, 1970/ज्येष्ठ 16, 1892
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1970/ JYAISTHA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 7 मई, 1970 तक प्रकाशित किये गये :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 7th May, 1970:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
150	S. O. 1519, dated 22nd April, 1970.	Election Commission of India.	Amendment in Notification No. 56/69-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969.
	का० आ० 1519, तारीख 22 अप्रैल, 1970।	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 56/69-2 (का० आ० 89) तारीख 4 जनवरी, 1969 में संशोधन करना।
151	S.O. 1520, dated 23rd April, 1970.	Ministry of Home Affairs.	Appointing a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice Kuppaswami Alladi, Judge, High Court, Andhra Pradesh.
152	S.O. 1521, dated 23rd April, 1970.	Ministry of Finance.	Appointing certain officers as Collectors of Customs for the areas mentioned in the table therein.
	एस० आ० 1521, तारीख 23 अप्रैल, 1970।	वित्त मंत्रालय	कुछ अधिकारियों को वर्णित क्षेत्रों के लिये सीमाशुल्क अधिकारी नियुक्त करना।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
153	S.O. 1522, dated 23rd April, 1970.	Ministry of Foreign Affairs	Nominating certain persons to serve on the Central Silk Board, with effect from the 9th April, 1970.
	S.O. 1522A, dated 23rd April, 1970.	Do.	Appointing Shri Mahabir Dass Member, Rajya Sabha and Member of the Central Silk Board as Vice-Chairman of the Central Silk Board.
154	S.O. 1523, dated 24th April, 1970.	Ministry of Finance.	Making an Order regarding Gold Control.
155	S.O. 1524, dated 24th April, 1970.	Election Commission of India.	Amendment to Notification No. 434/UP/67, dated 11th January 1967.
	एस० ओ० 1524, तारीख 24 अप्रैल, 1970 ।	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 434/उ०प्र०/67, तारीख 11 जनवरी, 1967 ।
156	S.O. 1525, dated 24th April, 1970.	Cabinet Secretariat.	The Government of India (Allocation of Business) (Eighth Amendment) Rules, 1970.
157	S.O. 1526, dated 25th April, 1970.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.	Granting recognition to the Bombay Oilseeds and Oils Exchange, Ltd., Bombay for a further period of one year from the 25th April, 1970 to the 24th April, 1971, in respect of forward contracts in ground-nut oil.
	का०आ० 1526, तारीख 25 अप्रैल, 1970 ।	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय	मुम्बई आयलसीड्स एण्ड आयलम एक्सचेंज, लिमिटेड, मुम्बई की भूगफली के तेल के अधिम संविदाओं की वावत और आगे एक वर्ष की कालावधि के लिये 25 अप्रैल, 1970 से 24 अप्रैल, 1971 तक मान्यता प्रदान करना ।
158	S.O. 1615, dated 28th April, 1970.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of the films as specified in the schedule therein.
	एस० ओ० 1615, दिनांक 28 अप्रैल, 1970 ।	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ।	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
	S.O. 1616, dated 28th April, 1970.	Do.	Approval of the film as specified in the schedule therein.
	एस० ओ० 1616, दिनांक 28 अप्रैल, 1970 ।	तदैव	अनुसूची में दी फिल्मों को स्वीकृत करना ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
159	S. O. 1617, dated 29th April, 1970.	Ministry of Finance.	The Gold Control (Grant of Certificates) Rules, 1970.
160	S.O. 1618, dated 29th April, 1970.	Ministry of Foreign Trade	Cancelling the notification No. S.O. 3792, dated 21st October 1968.
161	S.O. 1619, dated 29th April, 1970.	Election Commission of India.	Amendment in Notification No. 56/69-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969.
	एस० ओ० 1619, दिनांक 29 अप्रैल, 1970 ।	भारत निर्वाचित आयोग ।	अधिसूचना सं० 56/69-2 (का० आ० 89) तारीख 4 जनवरी 1969 में संशोधन करना ।
162	S.O. 1620, dated 30th April, 1970.	Do.	By-election to the House of the People from 74-Mathura Parliamentary Constituency.
	एस० ओ० 1620, तारीख 30 अप्रैल 1970 ।	तदैव	74-मथुरा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र से लोक सभा के लिये उप-निर्वाचन ।
163	S. O. 1621, dated 30th April, 1970.	Do.	By-election to the House of the People from 38-Gorakhpur Parliamentary Constituency.
	एस० ओ० 1621, दिनांक 30 अप्रैल, 1970 ।	तदैव	38-गोरखपुर संसदीय निर्वाचित क्षेत्र लोक सभा के लिये उप-निर्वाचन ।
164	S.O. 1622, dated 1st May, 1970.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of the film as specified in the schedule therein.
	एस० ओ० 1622 दिनांक 1 मई, 1970 ।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना ।
	S.O. 1623, dated 1st May, 1970.	Do.	Approval of the films as specified in the schedule therein.
	एस० ओ० 1623, दिनांक 1 मई, 1970 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
	S. O. 1624, dated 1st May, 1970.	Do.	Approval of the film as specified in the schedule therein.
	एस० ओ० 1624, दिनांक 1 मई, 1970 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
165	S. O. 1625, dated 1st May, 1970.	Election Commission of India.	By-election to House of the People from 51-Khunti (ST) Parliamentary Constituency in the state of Bihar.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	एस० ओ० 1625, दिनांक 1 मई, 1970 ।	भारत निर्वाचन आयोग	बिहार राज्य के 51 खूटी (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन ।
	S.O. 1626, dated 1st May, 1970.	Do.	Appointment of dates with respect for the above bye-election (S.O. 1625).
	एस० ओ० 1626, दिनांक 1 मई, 1970 ।	तदैव	उपर होने वाले उप-निर्वाचित के लिये तारीख नियत करना (एस० ओ० 1625) ।
	S. O. 1627, dated 1st May, 1970.	Do.	Fixing the hours for the above bye-election (S.O. 1625).
	एस० ओ० 1627, दिनांक 1 मई, 1970 ।	तदैव	उपर होने वाले उप-निर्वाचन के लिये समय नियत करना (एस० ओ० 1625) ।
166	S. O. 1628, dated 2nd May, 1970.	Ministry of Irrigation and Power.	Amendment in the notification No. S.O. 4054, dated the 6th October, 1969.
	एस० ओ० 1628, दिनांक 2 मई, 1970 ।	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	अधिसूचना सं० का० आ० 4055 तारीख 6 अक्टूबर, 1969 में संशोधन करना ।
167	S. O. 1629, dated 2nd May, 1970.	Election Commission of India.	Bye-election to the House of the People from the 25-Sultanpur Constituency.
	एस० ओ० 1629, दिनांक 2 मई, 1970 ।	भारत निर्वाचन आयोग	25-सुलताना पुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये उप-निर्वाचन ।
168	S. O. 1630, dated 4th May, 1970.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of the films as specified the schedule therein.
	एस० ओ० 1630 दिनांक 4 मई, 1970	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में दो गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
	S. O. 1631, dated 4th May, 1970.	Do.	Approval of the film as specified in the schedule therein.
	एस० ओ० 1631 दिनांक 4 मई, 1970 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना ।
169	S.O. 1632, dated 4th May, 1970.	Election Commission of India.	Amendment in its notification No 56/69-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	एस० ओ० 1632, दिनांक 4 मई, 1970 ।	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 56/69-2 (का० आ० 89) तारीख 4 जनवरी, 1969 में मंशोधन करना ।
170	S. O. 1633, dated 5th May, 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	The Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Product Control Order, 1970.
	एस० ओ० 1633, दिनांक 5 मई, 1970 ।	खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय ।	दिल्ली, मरठ और बुलन्दशहर दूध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश 1970 ।
171	S. O. 1695, dated 6th May, 1970.	Ministry of Law.	Bye-election to the House of the people from the 16-Buldana Parliamentary Constituency in the Maharashtra State.
	एस० ओ० 1695, दिनांक 6 मई, 1970 ।	विधि मंत्रालय ।	महाराष्ट्र राज्य में 16 बुल्डाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये उप-निर्वाचन ।
172	S. O. 1696, dated 6th May, 1970.	Election Commission of India.	Bye-election to the House of the People from the 18-Durg Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh.
	एस० ओ० 1696, दिनांक 6 मई, 1970 ।	भारत निर्वाचन आयोग	मध्य प्रदेश राज्य के 18 दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये उप-निर्वाचन ।
	S. O. 1697, dated 6th May, 1970.	Do.	Appointment of dates for the above bye-election (S.O. 1696).
	एस० ओ० 1697, दिनांक 6 मई, 1970 ।	तदैव	ऊपर होने वाले उप-निर्वाचन के लिये तारीख नियत करना (एस० ओ० 1696) ।
	S. O. 1698, dated 6th May, 1970.	Do.	Fixing the hours for the above bye-election (S.O. 1696).
	एस० ओ० 1698, दिनांक 6 मई, 1970 ।	तदैव	ऊपर होने वाले उप-निर्वाचन के लिये समय नियत करना (एस० ओ० 1696) ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
173	S. O. 1699, dated 7th May, 1970.	Election Commission of India	Appointing Shri B.L. Srivastava, Deputy Collector, Gorakhpur and Shri R. C. Shukla, Settlement Officer (Consolidation) Gorakhpur, as the Officers to assist the Returning Officer for 38-Gorakhpur Parliamentary Constituency.
	एस० ओ० 1699, दिनांक 7 मई, 1970 ।	भारत निर्वाचन आयोग	श्री बी० एल० श्रीवास्तव, डिप्टि कलेक्टर, गोरखपुर और श्री आर० सी० शुक्ल (बन्दोबस्त) अधिकारी (चकबन्दी) गोरखपुर की 38 गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को सहायता करने के लिये नियुक्त करना ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधितूचनाएं ।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 20th April 1970

S.O. 1987.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Krishna Nandan Prasad, R/o village Bandoh, P.O. Bhagarbigha District Patna (Bihar), a contesting candidate for the mid-term election to the Bihar Legislative Assembly from Bihar Assembly Constituency held in 1969 has failed to lodge on account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that no good reason or justification for such failure:

therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Krishna Nandan Prasad to be disqualified as and for being a member of either House of Parliament

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/195/69(80).]

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली 20 अप्रैल 1970

एस० ओ० 1987.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के लिए 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 195-बिहार निर्वाचनक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद निवासी—ग्राम बन्डौह, पो० आ० भागनबीथा, जिला पटना (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० सं०/195/69 (86).]

New Delhi, the 27th April 1970

S.O. 1988.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nilam Kumar Singh R/o village and P.O. Malaypur, District Monghyr (Bihar) a contesting candidate for the mid-term election to the Bihar Legislative Assembly held in 1969 from Jhajha Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nilam Kumar Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/170/69(87).]

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 1970

एस० ओ० 1988.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के लिए 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 170 साझा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, श्री नीलम कुमार सिंह निवासी ग्राम एवं पो० मलयपुर, जिला—मुंगेर (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नीलम कुमार सिंह को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० बिहार वि० सं०/170/69(87).]

New Delhi, the 30th April 1970

S.O. 1989.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Krishnamurti Chowdhary, R/o village and P.O. Badhauna, District Darbhanga (Bihar), a contesting candidate for the mid-term election to the Bihar Legislative Assembly held in 1969 from 99-Dalsinghsarai Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Krishnamurti Chowdhary, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/99/69(88).]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1970

एस० ओ० 1989.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 99 दालसिंग सराय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कृष्ण मूर्ति चौधरी निवासी ग्राम एवं पो० बड़ौता, जिला दरभंगा (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण, या न्यायोचित नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री कृष्ण मूर्ति चौधरी को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० सं०/99/69(88).]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

ORDERS

New Delhi, the 24th April 1970

S.O. 1990.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiv Charan S/o Shri Chiranj, R/o Town and Post Office Farah, District Mathura, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 365-Goverdhan Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Charan, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/365/69(27).]

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 1970

एस० नो० 1990.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 365—गोवर्धन सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव चरन मुकुत्र श्री चिरजी, निवासी ग्राम व पो० आ० फरह, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन, व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री शिव चरन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० सं०/365/69(27).]

New Delhi, the 1st May 1970

S.O. 1991.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Lal, S/o Shri Lohrey, R/o village and Post Office Jharotha, Tahsil Sadabad, District Mathura, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 370-Sadabad Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Lal, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/370/69(28).]

नई दिल्ली, 1 मई 1970

एस० श्री० 1991.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 370 सादाबाद सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबू लाल सुपुत्र श्री लोहरी, निवासी गांव व डा० शररौठा, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं :

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबू लाल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/370/69(28)]

S.O. 1992.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mannu Lal, S/o Shri Ram Narain, 75/158, Ranjit Purwa, Kanpur a contesting candidate for mid-term general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 293-Chamanganj constituency, held in February, 1969 has failed to lodge an account of his election expenses required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Munnu Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/293/69(29).]

एस० श्री० 1992.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी 1969 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए मध्यावधि साधारण निर्वाचन के लिए 293-चमनगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुन्नु लाल सुपुत्र श्री राम नारयण 75/158 रंजीत पुरवा, कानपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुन्नु लाल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० सं०/293/69(29).]

New Delhi, the 5th May 1970

S.O. 1993.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Sahai, S/o Shri Komil, R/o village Kartoli Post Office Fatehganj East, District Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 46-Dataganj Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder:

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Sahai, S/o Shri Komil, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/46/69(30).]

नई दिल्ली, 5 मई 1970

एस० ओ० 1993.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 46-दातागंज सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सहाय सुपुत्र श्री कोमिल, निवासी गांव करतौली, डा० फतेहगंज, पूर्वी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उस के पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सहाय सुपुत्र श्री कोमिल को संसद् के किसी भी सदन का या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/46/69(30).]

New Delhi, the 7th May 1970

S.O. 1994.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Moti Lal, S/o Shri Jagat Prasad, 105/322 Chamanganj (Shishamau) Kanpur District Kanpur (Uttar Pradesh) a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 292-Arya Nagar Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Moti Lal, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/292/69(31).]

नई दिल्ली, 7 मई 1970

एस० प्रो० 1994.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 292-आर्यनगर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोतीलाल सुपुत्र श्री जगत प्रसाद 105/322, चमनगंज, (शीशामऊ), कानपुर (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मोती लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/292/69(31).]

S.O. 1995.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Lakhan, R/o village Prathipura, Post Office Dadora, District Etawah (Uttar Pradesh), a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 309-Etawah Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Lakhan, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/309/69(32).]

एस० प्रो० 1995.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 309-इटावा सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम लखन निवासी गांव पृथीपुरा, डा० ददौरा, जिला इटावा, (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम लखन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/309/69(32).]

New Delhi, the 8th May 1970

S.O. 1996.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kalika Prasad, S/o Shri Pharai Ram, 27/42-Rotigodam, District Kanpur, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 294-Generalganj Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not rectified the defects in his account and has not given any reason or explanation for the failure, and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kalika Prasad, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/294/69(33).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

नई दिल्ली 8 मई 1970

एस० ओ० 1996.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 294-जनरलगंज सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कालिका प्रसाद सुपुत्र श्री फारइराम, 27/42, रोटी गोंदाम, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः; उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्पत्क सूचना दिए जाने पर भी अपने लेखे की त्रुटियों का परिशोधन नहीं किया है और इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयत्न स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है ;

अतः; अब, उक्त नियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री कालिका प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्गृहीत करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/294/69(33).]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 16th May 1970

S.O. 1997.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Rashid Sadar Ali Khan, Sri 18 Krishna Rajendra Market Madarasab Line, House No. 20, Bangalore-2, now residing at No. G-19, Albert Victor Road, I Main Road, Chamaraajpet, Bangalore-18 (Mysore State) a contesting candidate for the bye-election held in 1968, to the Mysore Legislative Assembly from 173-Hangal Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission, hereby declares the said Shri Abdul Rashid Sadar Ali Khan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MY-LA/173/68-Bye.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 मई 1970

एस० नो० 1997.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मैसूर विधान सभा के लिए 1968 में हुए उप-निर्वाचन के लिए 173-हंगल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल रशीद सदर अली खान, श्री कृष्ण राजेन्द्र मार्केट, मादरमाब लाईन, मकान सं० 20, बंगलोर-2; जो अब सं०-सी-19 ग्रुबर्ट विक्टर रोड 1 मेन रोड, धमारराजपेट, बंगलोर, 18 (मैसूर राज्य) में रह रहे हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे मध्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल रशीद सदर अलीखान को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं मसूर-वि० सं०/173/68-उप]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th May 1970

S.O. 1998.—In pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution and in supersession of all previous Notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs on the subject, the President hereby entrusts to the Governments of Punjab, Haryana and Maharashtra with their consent, the functions of the Central Government under section 7 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908).

[No. F. 26/2/70-GPA. II.]

C. B. BUDGUJAR, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1970

एस० ओ० 1998.—पविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में तथा इस विषय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 7 के अर्धीन केन्द्रीय सरकार के कार्य, पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र की सरकारों को, उनकी सहमति से एन्डोरा मौयते हैं।

[सं० एफ० 26/2/70—जी० पी० ए० 2.]

च० भ० बड़गूजर, अवसर सचिव।

New Delhi, the 29th May 1970

S.O. 1999.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby directs that the Lt. Governor of Delhi shall exercise the power to make rules in regard to the following matters, namely:—

- (i) the method of recruitment to the Judicial Services and Posts in connection with the affairs of the Union Territory of Delhi;
- (ii) the qualifications necessary for appointment to such services and posts; and
- (iii) the conditions of service of persons appointed to such services and posts for the purposes of probation, confirmation, seniority and promotion;

2. Any recruitment rules, including any rule relating to probation, confirmation, seniority and promotion, made in pursuance of this direction shall be subject to previous consultation with the High Court of Delhi.

[No. 1/2/70-DH(S).]

R. N. CHOPRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1970

एस० ओ० 1999.—पविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति एन्डोरा निदेश देते हैं कि उप-राज्यपाल, दिल्ली, निम्नलिखित मामलों से सम्बद्ध नियमों को बनाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात्:—

- () दिल्ली संव - शासि क्षेत्र के मामलों के सम्बन्ध में न्यायिक वाशों तथा पदों पर भर्ती की पद्धति;
- (ii) इन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं; और
- (iii) परिशिक्षा, पुष्टिकरण, वरीयता, और पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, इन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवा शर्तें।

2. परिक्षा, पुष्टिकरण, वरीयता और पदोन्नति सम्बन्धी किसी भी नियम समेत, जो भी भर्ती नियम, इस निदेशन के अनुसरण में बनाये जायेंगे, वे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण परामर्श से बनये जाएंगे।

[सं० 1/2/70—डी एच० (एस०).]

र० ना० शीपड़ा, उप-सचिव।

ORDER

New Delhi, the 26th May 1970

S.O. 2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1948 (25 of 1946), the Central Government hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the State of Orissa for the investigation of any of the offences specified below; namely:—

- (a) Offences under sections 47 and 55 of the Bihar and Orissa Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act 2 of 1915);
- (b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/8/67-AVD(II)]

B. C. VANJANI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई 1970

फा० आ० 2000.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार उड़ीसा राज्य पर, नीचे विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के अन्वेषण के लिए करती है, अर्थात्:—

- (क) बिहार और उड़ीसा उत्साद शुल्क अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम 2) की धाराओं 47 और 55 के प्रती के प्राप्ति ।
- (ख) खण्ड (क) में वर्णित एक या अधिक अपराधों के बारे में या के सम्बन्ध में प्रयत्न, दुरूपेण और षड्यंत्र तथा एक ही तथ्यों से उद्भूत एक ही व्यवहार के अनुक्रम में किया गया कोई अन्य अपराध ।

[संख्या 228/8/67-ए० वी० डी०(ii)]

बी० सी० वंजानी, अवर सचिव ।

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1970

एस० आ० 298.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (अथवा एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खण्ड 2 की धारा (क) के अनुसूचना में, केन्द्र सरकार इसके द्वारा, जर्मन लोक गणराज्य, पूर्वो बर्लिन, में भारत के व्यापार प्रतिनिधि को, इसी समय से, कौंसली अधिकारिता का कार्य करने का अधिकार देती है ।

- 2. उक्त अधिनियम के उद्देश्य से उक्त व्यापार प्रतिनिधि का पदनाम 'कौंसल' होगा ।

[सं० फा० डी० 114/5/69.]

पी० सी० भट्टाचार्य, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 16th May 1970

S.O. 2001.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply, till the 5th April 1971, to the Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur, in respect of the immovable property measuring 2.59 acres held by it at Palakuzha Village, Muvattupuzha Taluk, Ernakulam District, Kerala State.

[No. F. 15(11)-BC/70.]

K. YESURATNAM Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नयी दिल्ली, 16 मई, 1970

एस०ओ० 2001.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1959 का दसवां) की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर पर, जहां तक उनका सम्बन्ध, बैंक के अधिकार में पालाकुजा ग्राम, मूवत्तापुझा ताल्लुक, जिला एर्नाकुलम, केरल राज्य में स्थित 2.59 एकड़ अचल सम्पत्ति से है, 5 अप्रैल, 1971 तक लागू नहीं होंगे ।

[संख्या एफ० 15(11)—बी० सी०/70.]

क० यसरत्नम, असु-सचिव ।

(Department of Banking)

New Delhi, the 29th May 1970

S.O. 2002.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 22nd May, 1970

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	12,47,61,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	3,82,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	155,00,00,000	Small Coin	5,08,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	35,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:—	
		(a) Internal
		(b) External
		(c) Government Treasury Bills	7,98,26,000
		Balances Held Abroad*	114,09,74,000
		Investments**	96,93,00,000
		Loans and Advances to:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	75,00,00,000	(i) Central Government
		(ii) State Governments @	174,04,58,000
		Loans and Advances to:—	
Deposits:—		(i) Scheduled Commercial Banks†	285,66,30,000
(a) Government—		(ii) State Co-operative Banks††	226,14,69,000
(i) Central Government	106,46,30,000	(iii) Others	3,76,09,000
(ii) State Governments	5,73,95,000		

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 22nd day of May, 1970.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	12,47,61,000		Gold Coin and Bullion:—		
			(a) Held in India	182,53,11,000	
Notes in circulation	4039,03,14,000		(b) Held outside India		
Total Notes issued		4051,50,75,000	Foreign Securities	396,42,00,000	
			TOTAL		578,95,11,000
			Rupees Coin		55,03,49,000
			Government of India Rupee Securities		3417,52,15,000
			Internal Bill of Exchange and other commercial paper
TOTAL LIABILITIES		4051,50,75,000	TOTAL ASSETS		4051,50,75,000

Dated the 27th day of May, 1970.

B. N. ADARKAR,
Governor.

[No. F. 3(3)-BC/70.]

L. S. P. SARATHY, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

मई दिल्ली, 29 मई, 1970

एस० आ० 2002—22 मई 1970 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण ।

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	12,47,61,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,82,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	155,00,00,000	छोटा सिक्का	5,08,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	35,00,00,000	खरीद और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	75,00,00,000	(क) देशी
जमा राशियां :—		(ख) विदेशी
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	7,98,26,000
(i) केन्द्रीय सरकार	106,46,30,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	114,09,74,000
(ii) राज्य सरकारें	5,73,95,000	निवेश**	96,03,00,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	193,51,78,000	(i) केन्द्रीय सरकार को
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	9,66,49,000	(ii) राज्य सरकारों को @	174,04,58,000
		ऋण और अग्रिम :—	
		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	285,66,30,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	226,14,39,000
		(iii) दूसरों को	3,76,09,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
		(क) ऋण और अग्रिम:—	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	65,13,000	(i) राज्य सरकारों को	33,79,80,000
(iv) अन्य बैंक	21,53,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	14,97,81,000
(ग) अन्य	107,72,92,000	(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को
देय बिल	42,35,43,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,65,70,000
अन्य देयताएं	154,29,82,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	4,54,02,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :-	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	6,26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश
		अन्य आस्तियां	50,20,14,000
रुपये	1040,63,35,000	रुपये	1040,63,35,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 91,83,35,000 रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 27 मई, 1970।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मई 1970 की 22 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इस विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए			सोने का सिक्का और बुलियन		
नोट	12,47,61,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट	4039,03,14,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	396,42,00,000	
जारी किए गए कुल नोट		4051,50,75,000	जोड़		578,95,11,000
			रुपये का सिक्का		55,03,49,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां		3417,52,15,000
			विदेशी विनिमय बिल और		
			दूसरे वाणिज्य पत्र		..
कुल देयताएं		4051,50,75,000	कुल आस्तियां		4051,50,75,000

तारीख 27 मई, 1970।

बी० एन० अडारंकर,
गवर्नर।

[सं० एफ० 3(3)-बी० सी०/70]
एल० एस० पी० सार्थी, अनु-सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 19th May 1970

S.O. 2003.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises: Shri J. N. Sharma who is Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 20th May, 1970.

[No. 81(F. No. 404/104/70-ITCC).]

R. D. SAXENA, Dy. Secy.

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

आय-कर

नई दिल्ली, 19 मई 1970

एस० ओ० 2003.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जे० एन० शर्मा को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने का एतद्वारा प्राधिकार देती है।

1. यह अधिसूचना 20 मई 1970 से लागू होगी।

[सं० 81(एफ० सं० 404/104/70—आई० टी० सी० सी०)]

आर० डी० सक्सेना, उप सचिव।

(राजस्व और को बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1970

एस० ओ० 1523.—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के खण्ड F(ग) में निदिष्ट किसी व्यक्ति को उस खण्ड में निनिदिष्ट समय की परिसीमा से छूट दे दी जाएगी यदि वह इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर उक्त धारा 39 के उप नियम (1) में निनिदिष्ट प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन दे देता है।

सं० एफ० 1/23/70—जी० सी०]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1970

एस० ओ० 1617.—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 39 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) के साथ पठित धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये नियम स्वर्ण नियंत्रण (प्रमाणपत्रों का प्रदान) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम,” से स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) अभिप्रेत

(ख) “संप्रत्यावर्तित” से भारतीय मूल का वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विदेश में स्थायी निवासी रहते हुए उस देश को, भारत में स्थायी रूप से बस जाने की दृष्टि से, छोड़ देता है परन्तु यह तब जब कि ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़े गये देश में भारत सरकार के राजनयिक अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति के पास पोर्ट पर इस भाव का पृष्ठांकन हो कि वह भारत आने वाला एक सद्भावी प्रत्यावर्तित है, या जहाँ ऐसा कोई पृष्ठांकन नहीं किया गया हो वहाँ उसकी बाबत ऐसे अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित है कि वह भारत आने वाला एक सद्भावी प्रत्यावर्तित है ;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. वे व्यक्ति जिनको प्रमाण पत्र प्रदान किए जा सकते हैं —

धारा 39 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी का हो, अर्थात्:—

(क) वह संप्रत्यावर्तित जो उस देश में जहाँ से वह संप्रत्यावर्तित हुआ है, धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित, एक व्योहारी रहा हो परन्तु यह तब जब कि वह ऐसे संप्रत्यावर्तित से पूर्व कम से कम एक वर्ष उस देश में व्योहारी रहा हो।

(ख) वह व्यक्ति जो किसी ऐसे स्वर्णकार के कुटुम्ब का सदस्य होते हुए जिसने सरकार से स्वर्णकारों के पुनर्वास की किसी स्कीम के अधीन कोई उधार प्राप्त किया हो, ऐसे स्वर्णकार को उस के उस रूप में काम में भारत रक्षा नियम, 1962 के भाग 12क के प्रारम्भ से पूर्व कम से कम एक वर्ष की कालावधि के लिए सहायता की हो।

[स० फा० 1/22/70—जी सी II.]

जसजित सिंह, संयुक्त सचिव।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 23rd May 1970

S.O. 2004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 38 (F. No. 187/6/70-IT(AI), dated 28th March, 1970:

Against S. No. 13, Punjab, Jammu & Kashmir and Chandigarh, under column 3 of the Schedule appended thereto, the existing entry shall be substituted by the following:

“States of Punjab, Jammu & Kashmir and Union Territory of Chandigarh excluding Central Circles at Ludhiana, Amritsar and Srinagar and also excluding Income-tax Circle for Kangra and Chamba districts of Himachal Pradesh at Pathankot.”

This notification shall come into force on the 1st June, 1970.

[No. 85(F. No. 187/6/70-IT(AI).]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, 23 मई 1970

एस० ओ० 2004.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी दिनांक 28-3-0 की अधिसूचना सं० 38 (एफ० सं० 187/6/70-आई० टी० (ए-1) की संलग्न अनुसूची में एतद्-द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :

उक्त अधिसूचना की संलग्न अनुसूची के कालम 3 के अन्तर्गत क्रम सं० 13, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर और चण्डीगढ़ के सामने वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :

“लुधियाना, अमृतसर तथा श्रीनगर स्थित केन्द्रीय सर्किलों को छोड़कर तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों के लिए पठान चोट स्थित आयकर सर्किल को भी छोड़कर पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर राज्य और चण्डीगढ़ का संघ राज्य क्षेत्र।”

यह अधिसूचना 1 जून 1970 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 85(एफ सं० 187/6/70-आई० टी० ए० (I)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd May 1970

S.O. 2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 37 (F. No. 187/5/70-IT(AI), dated 31st March, 1970:

Against S. No. 7C, Haryana, Himachal Pradesh & Delhi III, under column 3 of the Schedule appended thereto, the following entry shall be added:

“8. Income-tax Circle for Kangra and Chamba Districts of Himachal Pradesh at Pathankot.”

This notification shall come into force on the 1st June, 1970.

[No. 84(F. No. 187/5/70-IT(AI).]

L. N. GUPTA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 मई, 1970.

एस० ओ० 2005.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी दिनांक 31-3-1970 की अधिसूचना सं० 37 (एफ० सं० 187/5/70-आई टी (ए-1), की संलग्न अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :

उक्त अधिसूचना की संलग्न अनुसूची के कालम 3 के अन्तर्गत क्रम सं० 7 ग, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली-III के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाय :

“8. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चम्बा जिलों के लिए पठानकोट स्थित आयकर सर्किल यह अधिसूचना 1 जून, 1970 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 84(एफ० सं० 187/5/70-आई० टी० (ए-1)]

एल० एन० गुप्ता, अवर सचिव।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 18th May 1970

S.O. 2006.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum), S.O. No. 427, dated January 1, 1970, under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the competent authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands, specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares, that the right of user in the said lands, specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

LAYING PIPELINE FROM GGS II TO FLARE POINT IN NAWAGAM OIL FIELD.

STAFFS : Gujarat.

DIST : Kaira

TALUKA : Matar

Village	S. No.	Hectare	Acre	P. Acre
Kathawada	388	0	0	75
"	405	0	10	52
"	406	0	4	57
"	407	0	1	25
"	409	0	2	75
"	408	0	7	63

[No. 20(3)/67-IOC/Lab. & Legis.]

M. V. S. PRASADA RAU, Under Secy.

(Department of Mines and Metals)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th April 1970

S.O. 2007.—In the Schedule attached to the Aluminium (Control) Order 1970, dated 20th April 1970, published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3—sub-section (ii) dated 20th March 1970, the word "Popes" occurring in the 14th line on page 421 thereof may be read as "Pipes".

[No. 5(28)-met/70(1).]

M. S. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

New Delhi, the 26th May 1970

S.O. 2008.—In exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following

rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules 1945, the same having been previously published as required by the said sections, namely:—

1. (i) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Second Amendment) Rules, 1970.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule R in clause IV of sub-paragraph (i) of paragraph 10 regarding "Labelling and Packing" for the words "twenty-four months" the following words shall be substituted, namely:—
"thirty-six months".

[No. F. 1-32/70-D.]

L. K. MURTHY, Under Secy.

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 25th May 1970

S.O. 2009.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-41/61-MI dated the 23rd July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification 'M.D.' granted by the University of Kansas, U.S.A. shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Ira Cox Jr. who possesses the said qualification is for the time being attached to the Reynolds Memorial Hospital, Washim, Akola Distt., Maharashtra for the purposes of charitable work,

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- (i) a further period of two years from the date of publication of this order in the official gazette, or
- (ii) the period during which Dr. Ira Cox Jr. is attached to the said Reynolds Memorial Hospital, Washim, Akola Distt., Maharashtra whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. F. 19-12/70-MPT.]

R. MURTHI, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 23rd May 1970

S.O. 2010.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).
- (3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant and the Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film	
1	2	3	4	5	6
1	Yasasvi Dayako	304.80M	Director of Information, Government of Gujarat, Sachivalaya, Ahmedabad-15	Documentary film, (for release in the Gujarat Circuit).	

[No. P. 28/1/70-FP-App. 1460].
K. K. KHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आवेष

नई दिल्ली 22 मई, 1970

एस० ओ० 2010.—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म की उसके गुजराती भाषा रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।
- (3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम	फिल्म का नाम	फिल्म को अवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकु-मेन्ट्री फिल्म है।	
संख्या		लम्बाई 35 मि० मी०			
1	2	3	4	5	6
1	यससवी दयाको (गुज-304.80 मीटर राती)	सूचना निदेशक, सरकार सचिवालय अहमदाबाद-15	गुजरात	डाकुमेन्ट्री फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिये)	

[सं० फईल 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट
क० क० खान, अवसर

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 18th May 1970

S.O. 2011.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5A of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has, with the approval of the Lt. Governor, Delhi constituted with effect from 25th September 1968 Yamuna Tat Vikas Kosh Board consisting of the following members, to administer the Yamuna Tat Vikas Kosh formed for the purpose of development of the ghats and the adjoining areas on both sides of the river Yamuna in Delhi:—

Chairman:

Chief Executive Councillor, Delhi.

Members:

1. Vice Chairman, D.D.A.
2. Engineer Member, D.D.A.
3. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi.
4. Chairman, Standing Committee, M.C.D.
5. The Mayor of Delhi.
6. Leader of the Opposition Group in the Corporation.

Hony. Secy.

Commissioner Implementation, D.D.A.

Hony. Treasurer.

Chief Accounts Officer, D.D.A.

[No. PA/CAO/5/50/68.]

M. L. MONGIA, Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 23rd May 1970

S.O. 2012.—In exercise of the powers conferred by section 72 of the Indian Patents and Designs Act, 1911 (2 of 1911), the Central Government hereby appoints the Deputy Director (Commercial Intelligence), Directorate of Industries, Shillong, Assam, as an authority for the purpose of the said section, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 681, dated the 23rd March, 1955, namely:—

In the said notification, after item (38) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—

“(39) The Deputy Director (Commercial Intelligence), Directorate of Industries (Assam), Shillong, Assam”.

[No. F. 33(7)-PP&D/70.]

HARGUNDAS, Under Secy.

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1970

अधिसूचना

एस०ओ० 2012.—भारतीय पेटेन्ट्स तथा डिजाइन्स अधिनियम, 1911, (1911 का 2) क द्वारा 72 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उप-निदेशक (वाणिज्यिक आसूचना)

उद्योग निदेशालय, शिलांग को उपर्युक्त धारा के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्राधिकारी नियुक्त करती है तथा भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 681, दिनांक 23 मार्च, 1955 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपर्युक्त अधिसूचना में मद (38) के पश्चात् तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात्:—

“(39) उप-निदेशक (वाणिज्यिक आसूचना),

उद्योग निदेशालय (आसाम), शिलांग, आसाम ।

[सं० फा० 33/(7)पी. पी. एण्ड. डी./70]

हरगुनदास, अव्वर सचिव ।

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 28th May 1970

S.O. 2013.—In exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Cars (Distribution and Sale) Control (Amendment) Order, 1970.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 7 of the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that the Controller, or in a State an officer appointed for the purpose by the Government of that State may, after making such inquiries as he deems fit, authorise the dealer by permit in writing to sell the motor car—

- (a) if the person whose name has been registered in the register of the dealer is dead, to the heir of such person;
- (b) if it is a company, registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and subsequent to the registration of its name in the register of the dealer,—
 - (i) it has changed its name, in the name of the company so changed;
 - (ii) it has transferred the undertaking, property and liabilities to any other company as a result of amalgamation sanctioned by the Court, in the name of the company to which the undertaking, property and liabilities have been transferred;
 - (iii) it is amalgamated as a result of the order of the Central Government made in that behalf, in the name of the company resulting from the amalgamation and specified in that order;
- (c) if it is a firm and subsequent to the registration of its name in the register of the dealer—
 - (i) it has changed its name, in the name of the firm so changed,
 - (ii) if it has been dissolved, in the name of any of the partners to whom the permit is transferred under the provisions of the agreement dissolving the partnership.”

[No. 8(34)/68-A.E.I. (I).]

S.O. 2014.—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Scooters (Distribution and Sale) Control Order, 1960, namely:—

1. (1) This order may be called the Scooters (Distribution and Sale) Control (Amendment) Order, 1970.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In clause 7 of the Scooters (Distribution and Sale) Control Order, 1980, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that the Controller, or in a State an officer appointed for the purpose by the Government of that State may, after making such enquiries as he deems fit, authorise the dealer by permit in writing to sell the scooter—

- (a) if the person whose name has been registered in the register of the dealer is dead, to the heir of such a person;
- (b) if it is a company, registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and subsequent to the registration of its name in the register of the dealer,—
 - (i) it has changed its name, in the name of the company so changed;
 - (ii) it has transferred the undertaking, property and liabilities to any other company as a result of amalgamation sanctioned by the Court, in the name of the company to which the undertaking, property and liabilities have been transferred;
 - (iii) it is amalgamated as a result of the order of the Central Government made in that behalf, in the name of the company resulting from the amalgamation and specified in the order;
- (c) if it is a firm and subsequent to the registration of its name in the register of dealer—
 - (i) it has changed its name, in the name of the firm so changed.
 - (ii) if it has been dissolved, in the name of any of the partners to whom the permit is transferred under the provisions of the agreement dissolving the partnership.”

[No. 8(34)/68-AEI (I).]

R. V. SUBRAHMANYAN, Jt. Secy.

(Department of Industrial Development)

(INDIAN STANDARD INSTITUTION)

New Delhi, the 27th April 1970

S.O. 2015—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of the Indian Standard, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. These modifications shall come into force with immediate effect :

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard, the Provisions of which have been Modified	Number(s) of the Existing Clauses Affected	Particulars of the Modifications made to the Provisions
1	2	3	4
1	IS : 3309-1965 Specification for soluble coffee chicory powder.	Table I regarding requirements for soluble french coffee powder.	(1) Table I, Sl. No. ii, Col. 2—Delete the word ‘Min’ (2) Table I, Sr. No. ii, Col. 3—Substitute ‘7.5 to 9.0’ for ‘7.5’

New Delhi, the 28th April 1970

S. O. 2016.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of the Indian Standard, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with immediate effect :

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard, the Provisions of which have been Modified	Number of the Existing Clause Affected	Particulars of the Modifications made to the Provisions of the Indian Standard
1	2	3	4
1	IS : 10-1964. Specification for plywood tea-chests (second revision)	Clause 5.1 and Table I	An additional size of tea-chests, namely of 40x40x60 cm dimensions has been included in clause 5.1 with resultant additions in Table I. This size is included in the draft third revision of IS:10—which has been issued for comments under Doc. No. BDC 20 (1768), February, 1970.

[No. CMD/13:4.]

New Delhi, the 18th May 1970

S. O. 2017.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended subsequently, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No CM/L-60, particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 16 May 1970 ;

Licence No. & Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence Cancelled	Relevant Indian Standard
CM/L-60 20-1-1958	The Standard Furniture Co. Ltd., Kallai, Kozhikode—(Kerala State)	Tea-chest Plywood Panels.	IS 10-1964 Specification for Plywood Tea-chests (Second Revision)

[No. CMD/55:60.]

S. O. 2018.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14th of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended subsequently, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-70, particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 16th May 1970 :

Licence No. & Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence Cancelled	Relevant Indian Standard
CM/L-70 7-2-1958	The Standard Furniture Co. Ltd., Chalakkudi (Kerala State)	Tea-chest Plywood Panels	IS : 10-1964 Specification for Plywood Tea-chests (Second Revision),

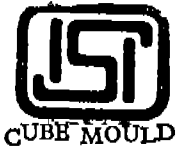
[No. CMD/55:70.]

New Delhi, the 22nd May 1970

S. O. 2019.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 16 May 1970 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description—the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS : 516 	Cube moulds for cement testing	IS : 516-1959 Methods of test for strengt of concrete	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col.(2), the number designation of the Indian Standard being super-scribed on the top side and the words 'CUBE MOULD' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9.]

S. O. 2010.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for Cube moulds for cement testing, details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 16 May, 1970.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cube moulds for cement testing	IS : 516-1959 Methods of test for strength of concrete.	One piece	50 paise

[No. CMD/13:10.]

A. K. GUPTA,
Deputy Director General.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION**

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 23rd May 1970

S.O. 202.—The following draft of rules further to amend the Vegetable Oils Grading and Marking Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published, as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 19th June 1970.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Vegetable oils Grading and Marking (Amendment) Rules, 1970.
2. In the Vegetable oils Grading and Marking Rules 1955, for Schedule IX, the following Schedule shall be substituted namely:—

SCHEDULE

Agmark grade designations and definitions of

Grade Designation	Description.	Clarity in height of column of oil (Inches through which Bourgeois print can be read in a 100 ml. Nessler tube)	Colour on Lovibond scale in 1" cell expressed as Y+5R (Not deeper than)	Specific gravity at 30°/30°C.	Refractive index at 40°C.
Medicinal*	The oil shall be the genuine refined product of Castor Seed (<i>Ricinus Communis</i>). It shall be free from admixture with other oils substance and also free from sediment and suspended matter.	4.0	3.5	0.954 to 0.960	1.4700 to 1.4740
First Special	Do.	4.0	3.7	0.954 to 0.960	1.4700 to 1.4740
First	The oil shall be the genuine product of castor seed (<i>Ricinus Communis</i>). It shall be free from admixture with other oil or substance and also free from sediment and suspended matter.	2.0	30	0.954 to 0.960	1.4700 to 1.4740
Commercial	—Do.—	..	40	0.954 to 0.960	1.4700 to 1.4740

*NOTE :—Medicinal Grade Castor Oil shall be graded under Agmark only if it

"Mix 5 ml. of oil with an equal volume of Carbon disulphide and add 1 ml. of Sulphuric acid and allow to stand for 24 hours. The mixture should be colourless or very slightly brown".

IX

quality for Castor Oil.

Saponifi- cation value	Iodine Value (Wij's Method)	Acetyl Value (Not less than)	Unsaponi- fiable matter (Not more than per cent)	Acid value (Not more than)	Certical solution tempera- ture in alcohol below	Moisture and im- purities (Not ex- ceeding per cent by weight)	Ash content max. per cent
177 to 185	82 to 90	143.0	0.8	2.0	0°C	0.25	0.05
177 to 185	82 to 90	143.0	0.8	2.0	0°C	0.25	0.10
77 to 185	82 to 90	143.0	1.0	4.0	—	0.75	0.10
177 to 185	82 to 90	143.0	1.0	6.0	—	1.0	..

conforms to the test given below.

phuric acid 95% W/W— the mixture may be coloured reddish brown but not blackish

[No. F. 10-3/69-L.A.]

जाख, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1970

का० आ० 2021.—वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये नियम का, जिसे कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिन्हन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बनाने की प्रस्थापना करती है, भिन्नलिखित प्रारूप, उक्त धारा द्वारा यथाअपेक्षित, एतद् द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, और एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर 19-6-70 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के बारे में उपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त हुए तो उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगा।

प्रारूप नियम

1. ये नियम वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिन्हन (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।
2. वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1955 में, अनुसूची 9 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

ग्रण्डी के तेल का एगमार्क श्रेणी अभिधान और अनुसूची IX

श्रेणी अभिधान	वर्णन	तेल स्तम्भ की ऊंचाई में क्लेरिटी (इंचों में 100 मि० नैसलर नली में जिनसे बोर- गियस प्रिंट पढ़ा जा सके)	लोवी बौंड स्केल पर 1 सेल-में वाई + 5 आर जैसा अभिव्यक्त रंग (से अधिक गहरा नहीं)	30°/30° सें० पर विशिष्ट घनत्व	40° से० पर अपवर्तनांक
1	2	3	4	5	6
*ओषधीय यह तेल ग्रण्डी के बीजों (रिकिनस कम्पुनिस) का असली परिष्कृत किया हुआ उत्पाद होगा। किसी अन्य तेल या पदार्थ के अधिमिश्रण से मुक्त होगा एवं तलछट और निलम्बित द्रव्य से भी मुक्त होगा।		4.0	3.5	0.954 से 0.960	1.4700 से 1.4740

IX

उसकी क्वालिटी की परिभाषा

साबुनी- करणमान	आयोडिन- मान (विज्स- पद्धति)	ऐसिटिल- मान (से अन्युन)	असम्बुनी- करणीय द्रव्य (प्रतिशत से अनधिक)	ऐसिड- मान (से अनधिक)	ऐलकोहल में सेंटी- कल घोल तापमान इससे कम	नमी एवं अशुद्धता (वजन में प्रतिशत से अनधिक)	भस्ममान अधिकतम प्रतिशत
7	8	9	10	11	12	13	14
177 से 185	82 से 90	143.0	0.8	2.0	0° से	0.25	0.05

1	2	3	4	5	6
प्रथम विशेष	—यथोक्त—	4.0	3.7	0.954 से 0.960	1.4700 से 1.4740
प्रथम	यह तेल अण्डों के बीजों (रिकिनस कम्पुनिस) का असली उत्पाद होगा। यह किसी अन्य तेल या पदार्थ से अधिमिश्रण से मुक्त होगा एवं तलछट और निलम्बित द्रव्य से भी मुक्त होगा।	2.0	30	0.954 से 0.960	1.4700 से 1.4740
वाणिज्यिक	—यथोक्त—	—	40	0.954 से 0.960	1.4700 से 1.4740

*टिप्पणी—श्रीषष्ठीय श्रेणी का अण्डों का तेल ऐगमार्क के अन्तर्गत केवल उसी स्थिति में श्रेणीकृत समान मात्रा में कार्बन डाइसल्फाइट मिलाइए और उसमें 1 मिली लीटर हो सकता है लेकिन कृष्ण—बभ्रु नहीं। ”

#	8	9	10	11	12	13	14
177 से	82 से	143.0	0.8	2.0	0°सें०	0.25	0.10
185	90						
177 से	82 से	143.0	1.0	4.0	—	0.75	0.10
185	90						
177 से	82 से	143.0	1.0	6.0	—	1.0	—
185	90						

किया जायगा जब वह निच दिए गए परीक्षण के अनुरूप हो "5 मिली लीटर तेल में सल्फ्यूरिक एसिड 95 प्रतिशत डबल/डबल मिलाए मश्रण का रंग रहता न- भरा।

[सं०फा० 10-3/69-एल०ए०]

बी० के० मलिक, उप सचिव ।

CORRIGENDUM*New Delhi, the 23rd May 1970*

S.O. 2022.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) No. S.O. 535 published in the Gazette of India [Part II, Section 3 (ii)] page 805 dated the 14th February, 1970, the following correction is notified:—

Word "Post" may be inserted between the words 'by' and 'weighing' occurring in clause (4) so as to read as "A flat rate of 35 paise on each packet of wool sample despatched by post weighing over $\frac{1}{2}$ kilogram and upto $2\frac{1}{2}$ kilograms irrespective of weight or grade".

[No. 8-1/69-L.A.]

V. K. MALIK, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 22nd May 1970

S.O. 2023.—M/s. Scientific Instrument Co., Ltd., New Delhi were granted an import licence No. G/DG/2106404/C/XX/27/H/25, dated 3rd April, 1968, for Rs. 39,530. They have applied for a duplicate licence (both Customs and Exchange Control purpose copies) on the ground that the original custom and exchange purpose copies have been lost without having been registered with any Customs Authority and unutilised. In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Custom and Exchange Control purpose copies of the licence No. G/DG/2106404/C/XX/27/C/H/25, dated 3rd April, 1968, have been lost and that duplicate copies thereof should be issued to the applicant.

In exercise of the powers conferred on me by clause 9(cc) of the Import (Control) order No. 17/55, dated 7th December, 1955, as amended from time to time, the undersigned cancels the Customs and Exchange Control copies of import licence No. G/DG/2106404/C/XX/27/C/H/25, dated 3rd April, 1968, for Rs. 39,530 for the import of L and N No. 8059 B Muller Bridge etc., under I.T.C. Schedule S. No. 78(IX)/V issued in favour of M/s. Scientific Instruments Co., Ltd., New Delhi.

[No. 47-S/Cont/67-68/GLS/94.]

G. D. BAHL,
Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 28th May 1970

S.O. 2024.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th June, 1970 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in FARRUKHABAD Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-51/70-PHB.]

D. R. BAHL, Assistant Director General.(PHB)

संचार विभाग
(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 मई, 1970

एस० ओ० 2024.—स्थायी आदेश क्रम संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खंड III के पैरा

(क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने फरुखाबाद टेलीफोन केन्द्र में 16-6-70 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-51/70 पी०एच०बी०]

डी० आर० बहल,

[सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी०)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 25th May 1970

S.O. 2025.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 39-TAG (1)/70 dated the 27th February, 1970 published in the Extraordinary Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (ii) under S.O. No. 829, the Central Government hereby cancels the enforcement of section 25 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1969 (56 of 1969) with effect from the 2nd March, 1970.

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the said Act, the Central Government, hereby appoints 1st day of November, 1970 as the date on which the provisions of section 25 of the said Act shall come into force.

[No. 39-TAG(13)/70.]

पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 मई, 1970

एस० ओ० 2025.—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 39-टी०ए०जी० (1)/70 तारीख 27 फरवरी 1970 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग, 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का० आ० सं० 829 के अधीन प्रकाशित हुई है, के आंशिक उपान्तर में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मोटरगाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 56) की धारा 25 के प्रवर्तन का 2 मार्च 1970 से, रद्द करती है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नवम्बर, 1970 के पहले दिन को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 25 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[सं० 39-टी०ए०जी० (13)/70]

New Delhi, the 26th May 1970

S.O. 2026.—The following draft rules further to amend the Inter-State Transport Commission Rules, 1960, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 63C of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) is hereby published as required by sub-section (1) of section 133 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Central Government on or after the 20th June 1970.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft before the date specified above will be duly considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Inter-State Transport Commission (Amendment) Rules, 1970.

2. In rule 24 of the Inter-State Transport Commission Rules, 1960:—

(i) in sub-rule (1), for the words “thirty days” wherever they occur the words “sixty days” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5) An appeal preferred under sub-rule (1) shall bear a court fee-stamp of ten rupees.”

[No. 39-TAG(10)/70.]

K. C. JOSHI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1970

एस०ओ० 2026.— अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिन्हें केन्द्रीय सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63ग (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने की प्रस्थापना करती है उक्त अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर केन्द्रीय सरकार 20 जून, 1970 को या के पश्चात् विचार करेगी।

किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के बारे में जो कोई आक्षेप या सुझाव ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होगा उस पर केन्द्रीय सरकार सम्यक रूप से विचार करेगी।

प्रारूप नियम

अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग (संशोधन) नियम, 1970

1. ये नियम अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।
2. अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग नियम, 1960 के नियम 24 में:

(i) उप-नियम (1) में ‘तीस दिन’ शब्दों जहाँ वहाँ भी वे आए हों के स्थान पर “साठ दिन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

“(5) उप नियम (1) के अधीन की गई अपील पर वस रुपये का न्यायालय फीस स्टाम्प होगा।

[सं० 39-टी० ए० जी० (10)/70]

के० सी० जोशी, उप-सचिव।

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th May 1970

S.O. 2027.—In pursuance of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1934, the Central Government hereby establishes a Seamen's Employment Board (Foreign-going) at the Port of Calcutta for a period of two years with effect from the date of issue of this Notification and appoints the following persons to be members thereof, namely:—

- | | | |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. The Director-General of Shipping. 2. The Deputy Director General of Shipping, in charge of Seamen's Employment Office, Calcutta. 3. The Labour Commissioner, West Bengal, Calcutta. 4. The Shipping Master, Calcutta. 5. The Principal Seamen's Welfare Officer, Calcutta. 6. The Director, Seamen's Welfare ment Office, Calcutta. | } | <p>Members
representing
Government.</p> |
|---|---|---|

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 7. Capt. A. B. McSweeney. | } | Members
Shipowners
representing |
| 8. Shri P. I. D. Barty. | | |
| 9. Shri R. N. Ghosal. | | |
| 10. Shri N. K. Sen. | | |
| 11. Shri K. Raghavan. | | |
| 12. Capt. C. G. Bhoot. | } | Members
representing
Seamen. |
| 13. Shri Asit Mitra. | | |
| 14. Shri Bejoy Mukerjee. | | |
| 15. Shri Ajit Chakraborty. | | |
| 16. Shri Subhrendu Chatterjee. | | |
| 17. Shri Sunil Das. | | |
| 18. Shri Rattan Ballav. | | |

2. The Director-General of Shipping shall be the Chairman of the Board. The Deputy-Director-General of Shipping, in charge of Seamen's Employment Office, Calcutta shall be the Vice-Chairman of the Board.

3. The Director, Seamen's Employment Office, Calcutta shall act as the Secretary of the Board.

[No. 15-MT(2)/69.]

J. K. BHATTACHARYA, Dy. Secy..

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 मई, 1970

का० ग्रा० 27.—भारतीय वाणिज्यिक पोतपरिवहन (नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता) नियम, 1954 के नियम 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कलकत्ता पर्टेन पर दो वर्ष की अवधि के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक नाविक रोजगार बोर्ड (विदेशगामी) नियुक्त करती है तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को उसका सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- | | | |
|--|---|---|
| 1. पोतपरिवहन के महानिदेशक, | } | सरकार का प्रतिनिधिरूप करने वाले सदस्य |
| 2. पोतपरिवहन के उप महानिदेशक,
नाविक रोजगार कार्यालय,
कलकत्ता, के कार्यभारी । | | |
| 3. श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता । | | |
| 4. पोतपरिवहन मास्टर, कलकत्ता । | | |
| 5. मुख्य नाविक कल्याण अधिकारी, कलकत्ता । | | |
| 6. निदेशक, वाणिज्यिक रोजगार कार्यालय कलकत्ता । | | |
| 7. कप्तान ए० बी० मेकस्वीनी । | } | पोतपालिकों का प्रति-निधित्व करने वाले सदस्य |
| 8. श्री पी० आई० डी० वार्टी । | | |
| 9. श्री आर० एन० घोषाल । | | |
| 10. श्री एन० के० सेन । | | |
| 11. श्री के० राघवन । | | |
| 12. कप्तान सी० जी० भूट । | } | नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य |
| 13. श्री असित मित्रा । | | |
| 14. श्री विजय मुकरजी । | | |
| 15. श्री प्रजीत चक्रवर्ती | | |
| 16. श्री सुभेन्दु चटरजी । | | |
| 17. श्री सुनील दास । | | |
| 18. श्री रत्न बल्लभ । | | |

2. पोत परिवहन के महानिदेशक इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। पोतपरिवहन के उप-महानिदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता, के कार्यभारी, इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे।

3. निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता, इस बोर्ड के सचिव के रूप में काम करेंगे।

[सं० 15-एम० ट० (2)/69]

जे० के० भट्टाचार्य, उप सचिव।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 20th May 1970

S.O. 2028.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the Industrial dispute between the employers in relation to the managements (1) M/s. India Cement Limited, Sankari West Post Office, Salem District, (2) Messrs Star Construction and Transport Company, Sankari West and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th May, 1970.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

Saturday, the 2nd day of May, 1970.

PRESENT:

Thiru S. Swamikkannu, B.Sc., M.L., Industrial Tribunal, Madras.

I.D. No. 21 of 1969

(In the matter of the dispute for adjudication u/s. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 between the workmen and the managements of (1) M/s. India Cement Ltd., Sankari West and (2) M/s. Star Construction and Transport Company, Sankari West).

BETWEEN:

1. The General Secretary, The India Cements Employees Union, Sankari West Post Office, Salem District.
2. The Secretary, India Cement and Mining Workers' Union, Karumapurathanur, Sankari West Post Office, Salem District.

AND

1. The General Manager, M/s. India Cement Ltd., Sankari West.
2. M/s. Star Construction and Transport Company, Sankari West, Salem District (Impleaded as per order dated 2nd May, 1970, in Misc. App. No. 198/70 in I.D. No. 21 of 69):

REFERENCE:

Order No. 36/48/68-LR-I, dated 20th February, 1969 of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiru G. Venkataraman, Advocate of M/s. Aiyer and Dolla, Advocates for the Union No. 1, Thiru S. Ramaswamy, Advocate for Union No. 2 and of Thiruvalargal M. R. Narayanaswamy and D. Meenakshisundaram, Advocates for the management No. 1 and Thiruvalargal T. Raghavan and T. K. Seshadri, Advocates for the management No. 2, upon perusing the reference and all other material papers on record and the parties having filed a joint memorandum of settlement and clarification and recording the same, this Tribunal made the following:—

AWARD

This is a Central Government reference in respect of an industrial dispute between the management of M/s. India Cements Limited, Sankari West Post Office

(District Salem) and their workmen in respect of the matters specified in the schedule to the reference.

2. The India Cements and Mining Workers Union, Union II herein, alone filed a claim statement putting forth the demands of the workmen. Union No. 1 did not file any claim statement. No counter statement also has been filed in this case.

3. On 29th April, 1970, the learned counsel for the managements, viz., M/s. India Cements and M/s. Star Construction, as well as the learned counsel for the Unions, India Cements Employees Union and India Cements and Mining Workers Union, appear and represent that the parties to the I.D. have settled all the issues referred in this I.D. and the settlement dated 7th April, 1969 and the clarification dated 9th August, 1969 may be recorded. The case was posted to 2nd May, 1970 for passing orders on the application for impleading the second management.

4. Today, application for impleading the Star Construction and Transport Company is allowed. The memo of settlement dated 7th April, 1969 and the clarification dated 9th August, 1969 thereto are recorded. An award is passed in terms of the settlement as well as the clarification which will form part of the award.

List of Witnesses and Documents marked for both sides.

Nil.

(Sd.)/- S. SWAMIKKANNU,
Industrial Tribunal.

Memorandum of Settlement (A)

Whereas the India Cements Employees' Union had raised demands relating to:—

(1) Abolition of contract system of labour adopted by M/s. The India Cements Ltd., Sankari West, for quarrying and transporting limestone from their Mines to their Factory at Sankari.

(2) Employment of above workmen directly in the regular services of M/s. The India Cements Ltd.

(3) Reinstatement of Sri S. Kandasamy, Driver (2) Sri M. V. Bhaskaran, Driver (3) Sri P. R. Narayanan, Mate, (4) Sri C. Selvadās, Token No. 518, (5) Sri Raman Chetty, Token No. 22, (6) Sri Madappan, T. No. 603 and (7) Sri S. Balaraj, T. No. 31.

(4) Absorption as Mates in the services of M/s. Star Construction and Transport Co., the following six workmen:

- (1) Shri Ramaswamy.
- (2) Shri Kamalasekaran.
- (3) Shri Natarajan.
- (4) Shri C. Ramaswamy.
- (5) Shri Kuppuswamy.
- (6) Shri Palaniappan.

(5) Payment of 20 per cent. of the total wages as annual bonus for the year 1967-68 by M/s. Star Construction and Transport Company as was paid to the factory workers of India Cements, the principal employer.

Whereas following the failure of conciliation on the above issues in dispute, they have been referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Madras.

Whereas during the pendency of the said adjudication proceedings, the parties continued to negotiate;

Whereas the Management of India Cements Ltd., pointed out that their expansion programme has been considerably delayed owing to causes beyond their control;

Whereas the Star Construction and Transport Co., said that in consequence of the reduced demand by The India Cements, Ltd., they are faced with surplus labour in all categories;

Whereas Star Construction and Transport Co., further said that consequent on the breakdown and absolute condition of some of their lorries, they had reported to giving on contract the transport work of limestone and rejects;

Whereas the equipment of The India Cements Ltd., in their Crusher Plant is such that they could not take delivery of limestone supplies before 7.00 A.M. or after 7.00 P.M. on the week days;

Whereas the India Cements Ltd., pointed out that the contract now subsisting between themselves and Star Construction and Transport Co., is valid upto 31st October, 1973;

Whereas they further pointed out that it will not be possible for them to terminate the contract in the middle;

Whereas the workmen in reply said that the work of quarrying and supply of limestone for the Cement Industry is an integral part of the process of cement production;

Whereas the nature of work in the quarries is regular and the volume of employment is predicable and therefore the workmen in this process should be taken under the direct employment of India Cements and employed not through contractors;

Whereas the parties are anxious to negotiate and settle all outstanding disputes with a view to improve the atmosphere at the quarries, thereby leading to improvement in production and keeping good relations and discipline;

It has been agreed as follows:—

Terms of Settlement

- (1) That the existing contract between Star Construction and Transport Co., and the India Cements, Ltd., will be allowed to run for the unexpired portion of the same i.e., upto 31st October, 1973, whereafter the India Cements Ltd., agree that the employees now employed through the Star Construction and Transport Co., will be absorbed suitably as regular employees of the India Cements, Ltd.
- (2) Till that period, all employees borne on the musters of Star Construction and Transport Co., viz.,

Breakers.	..	688
Drilling Section.	..	103
Blasters	..	42
Loading workers.	..	138
Drivers, Helpers.	..	82
Attenders, etc.	..	9
Supervisory staff.	..	17
Clerical staff.	..	28
Watch and Ward staff.	..	14
Maistry.	..	15

1136

totalling 1136 workmen, plus an additional 142 breakers to be absorbed as regular employees of the Star Construction and Transport Co., from employment under sub-contractors, plus the seven persons referred to in para 9 of this settlement, plus the three mates referred in para 12 of this settlement, viz., 1288 in all, will from the total strength of Star Construction and Transport Co. with effect from the date of this agreement.

(3) All the said workers (1288) referred to in the previous para employed by Star Construction and Transport Co., will be eligible for the same terms and conditions of employment, including basic pay, dearness allowance, etc., benefits and other amenities, as are available to the regular employees of the India Cements Ltd., Sankari West, from the date of this settlement.

(4) The question of supply of uniforms to the employees under Star Construction and Transport Co., will however be limited to Transport Drivers immediately and later extended to blasters at the end of one year from date.

(5) In regard to transport of limestone from the quarry to the factory, which is a raw material for the Industry, it will be carried out by the direct employees of the Star Construction and Transport Co., till October 31, 1973. Any part of this work now done by the sub-contractors will be taken over in a phased manner by Star Construction and Transport Co., before August, 1969.

(6) It shall, however, be open to Star Construction and Transport Co., to arrange for the removal of overburden and the transport of rejects and other waste products, through sub-contractors.

(7) Star Construction and Transport Co., shall maintain a list of workmen employed by sub-contractors with their seniority, furnishing a copy of the same union; and as and when, vacancies arise either by natural causes or on account of expansion, the workmen from sub-contractor's list will be absorbed as employees of Star Construction and Transport Co., in a phased programme within a period of four years from date.

(8) Both the contract and sub-contract system of employment will come to an end by 31st October, 1973.

(3) With regard to the demand for reinstatement of the following workers:—

- (1) Shri R. Kandasamy, Driver.
- (2) Shri K. V. Bhaskaran, Driver.
- (3) Shri P. R. Narayanan, Mate.
- (4) Shri C. Selvadas, Token No. 518.
- (5) Shri Raman Chetty, Token No. 22.
- (6) Shri Madappan, Token No. 603.
- (7) Shri S. Balaraj, Token No. 31.

It is agreed that they will be reinstated with effect from the date of this agreement. The period of non-employment of the above seven workmen will not operate as break in service and the Star Construction and Transport Co., will pay as ex-gratia Rs. one hundred to each of them within a month from date.

(10) With regard to termination of the services of Sri Mari, with effect from 31st August, 1968, the management agrees to give him some suitable alternative employment, increasing the strength to 1289.

(11) With regard to absorbing the following six workmen as Mates:

- (1) Shri Ramasamy.
- (2) Shri Kamalasekaran.
- (3) Shri Natarajan.
- (4) Shri C. Ramaswamy.
- (5) Shri Kuppusamy.
- (6) Shri Palaniappan,

It is agreed that the following three, viz.,

- (1) Shri Natarajan.
- (2) Shri C. Ramaswamy.
- (3) Shri Ramaswamy.

will be absorbed as Mates with effect from the date of this agreement and the remaining three will be absorbed as and when suitable vacancies arise.

(12) In regard to payment of bonus for the year ended 30th June, 1968, parties feel that they could not reach a settlement, as the gap between the Union's expectations and the offer of the management was too wide. Parties therefore agree to leave it to be decided by the Tribunal.

(13) Parties agree that this agreement will be filed before the Hon'ble Industrial Tribunal, Madras, jointly with a prayer that an award may be passed in terms hereof.

Dated this the 7th day of April, 1969, at Madras.

(Sd.)/-

President, 7-4-69.

(Sd.)/- S. V. PALANIAPPAN, Secretary.
3-4-69.

For the India Cements Employees' Union.

Sankari West.

Witness:—

Sd./-

For The India Cements Ltd.

Sd./- N. SRINIVASAN.

For Star Construction and Transport
Co., Sankari, West.

Sd./-

Minutes of discussion between the Management of Star Construction and Transport Co., and the India Cements Ltd., and the workers of S.C.T. represented by The India Cements Employees Union, held on the 9th August, 1969.

Present:

1. Mr. J. H. Tarapore.
2. Mr. T. P. Rao
3. Mr. K. S. Narayanan.
4. Mr. N. Srinivasan.
5. Mr. T. S. Subramaniam.
6. Mr. G. Ramanujam.
7. Mr. Narayanan.
8. Mr. S. K. Palaniappan.
9. Mr. T. P. Natesan.
10. Mr. A. Kandaswamy.

In response to the Management's request for clarification of their rights under the Agreement dated 7th April, 1969 for suitable redeployment of surplus persons in terms of agreed workload, it was agreed that such of these workmen who are found surplus to the requirements of the Management on the basis of agreed workloads will not be retrenched but will be given suitable alternate employment without any reduction in emoluments or grades. In this process only the junior most of the category will be thus redeployed.

In respect of the loaders' workload in the Mottalayanur quarry, it is agreed that if the Management maintains the same frequency of loading as in the Karumapurathanur quarry and also keep the stones on both sides of the lorry, same gang strength with more or less the same height of vehicles, the workload in the Mottalayanur quarry for the loaders will be the same as in Karumapurathanur quarry, viz., 8.5 tonnes.

In regard to workers who are brought for loading work for the first time, one month's time shall be given to enable them to familiarise themselves with the work and to give the required workload. In view of this understanding, the Management will pay the Breakers who have been asked to work as loaders their full wages up-to-date condoning the fall in individual workload so far.

It is agreed that the Management will put in 8 additional lorries within the next six months, i.e., before the end of February, 1970. At no time during the currency of the said Agreement dated 7th April, 1969, the Management shall engage more than 10 hired lorries. However, upto the end of February 1970, marginal adjustments in the number of hired lorries could be made.

Sd./- S. K. PALANIAPPAN

9-8-69

Sd./- T. P. RAO,

Sd./- N. SRINIVASAN

[No. F. 36/48/68-LR-IV.]

New Delhi, the 1st June 1970

S.O. 2029.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri F. Jeejeebhoy, Barrister-At-Law, Advocate of the Supreme Court and arbitrator care of Mercantile Bank Limited, Connaught Place, New Delhi-1, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Associated Cement Companies Limited, Nowrozabad Colliery, Post Office Nowrozabad, District Shahdol, Madhya Pradesh and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th May, 1970.

ARBITRATION AWARD

In the matter of Associated Cement Companies Limited, Nowrozabad Colliery.

AND

Their workmen represented by the Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh.

PRESENT.

Mr. F. Jeejeebhoy, Barrister-at-law, Arbitrator.

For the employer.—Mr. I. M. Nanavati, Advocate, and Mr. M. S. Kapur, Personnel Officer.

For the workmen.—Mr. K. B. Chougule, General Secretary, Mr. Hukam Chand Gureja, President and Mr. G. R. Swamy, Secretary, Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh, Nowrozabad.

AWARD—In the matter of Shri Bhim Sen.

By their Agreement dated 28th January, 1965 under Section 10A of the Industrial Disputes Act between The Associated Cement Companies Ltd. Nowrozabad Colliery of the one part and the workmen as represented by Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh of the other part, the parties agreed to refer certain disputes to my arbitration including the complaint under Section 33A of Bhim Sen. The said Arbitration Agreement has been published in the Gazette of India. Part II, Section 3(ii) dated 20th February 1965 at pages 733 to 735.

2. This is a complaint under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 filed by Shri Bhim Sen son of Sudershan Prasad. The said complaint was originally filed by Shri Bhim Sen on 12th February 1964 before Central Government Industrial Tribunal Bombay, arising out of Ref. No. CGIT-43 of 1962 pending before the said Tribunal. Later the said complaint was withdrawn by the parties and referred to my arbitration under Sec. 10A of the I.D. Act, by the Arbitration Agreement dated 28th January, 1965.

3. The issue referred to me by the aforesaid Arbitration Agreement is; whether the complaint filed by Shri Bhim Sen before the CGIT Bombay under Sec. 33A of the I.D. Act and numbered by the said Tribunal as complaint No. 11 of 1964 as and when originally filed is maintainable under Sec. 33A and if so to what relief the concerned workman is entitled.

4. Since under the aforesaid Arbitration Agreement several other disputes were also referred to my arbitration, the Union had filed a composite Written Statement in all the matters and paragraphs 74 to 77 relate to the case of Shri Bhim Sen. The Company had filed its Written Statement dated 28th June, 1965, before me.

5. When the matter came up for hearing before me at Delhi on 5th March, 1970, Mr. Chougule stated that the Company in its Written Statement had taken the plea that since Bhim Sen was not concerned in any of the disputes, his complaint under Sec. 33A was not maintainable. Mr. Chougule further stated that he had gone through the terms of the pending references and found that Bhim Sen was not concerned in any of the disputes pending. He therefore prayed that it may be held that the complaint of Bhim Sen was not maintainable under Sec. 33A so that the union or the workman may be free to raise an industrial dispute. Mr. Nanavati, appearing for the Company stated that in the Written Statement of the Company filed before the Arbitrator no such contention was taken that Bhim Sen was not concerned in any of the disputes pending before the Tribunal at the time when he had filed the complaint under Sec. 33A. It was only stated that the Company did not admit to have contravened the provisions of Sec. 33. Mr. Nanavati further stated that the Company had also filed Written Statement

on the merits of the dispute and the Company had no objection if the merits of the complaint are decided in these arbitration proceedings; the union's attempt to withdraw from the arbitration and to take up the industrial dispute as to the dismissal of Bhim Sen after several years would put the Company into unnecessary costs; and the union can have it done without pressing their contention as now raised that the complaint was not maintainable. However, Mr. Chougule stated that the terms of reference state as a preliminary condition that the arbitrator should decide whether the complaint under Sec. 33A was maintainable; and that it was obvious that the complaint was not maintainable and, therefore, any decision on the merit would be without jurisdiction and illegal and would lead to unnecessary and prolonged litigation. Mr. Chougule stated that the preliminary point goes to the very root of the matter and upon its decision the arbitrator could derive the jurisdiction.

6. Both the parties agreed that Shri Bhim Sen was not concerned in any of the pending proceedings at the relevant time.

7. It, therefore, appears that the complaint under Sec. 33A of Shri Bhim Sen now before me is not founded on any legal necessity and accordingly I hold that the complaint is not maintainable under Sec. 33A of the I.D. Act.

Dated at New Delhi this the 1st day of May, 1970.

Sd./- F. JEEJEEBHoy,
Arbitrator.

[No. 5/1/64-LR.II(1).]

S.O. 2030.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri F. Jeejeebhoy, Barrister-At-Law, Advocate of the Supreme Court and arbitrator, care of Mercantile Bank Limited, Connaught Place, New Delhi-1, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Associated Cement Companies Limited, Nowrozabad Colliery, Post Office Nowrozabad, District Shahdol, Madhya Pradesh and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th May, 1970.

ARBITRATION AWARD

In the matter of Associated Cement Company Limited, Nowrozabad Colliery.

AND

Their workmen represented by the Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh.

PRESENT:

Mr. F. Jeejeebhoy, Barrister-at-law, Arbitrator.

For the employers.—Mr. I. M. Nanavati, Advocate, and Mr. M. S. Kapur, Personnel Officer.

For the workmen.—Mr. K. B. Chougule, General Secretary, Mr. Hukum Chand Gureja, President and Mr. G. R. Swamy, Secretary, Nowrozabad Colliery, Mazdoor Sangh, Nowrozabad.

AWARD: In the matter of Shri Inderpal.

By their Agreement dated 28th January, 1965 under Section 10A of the Industrial Disputes Act 1947 between the Associated Cement Companies Ltd. Nowrozabad Colliery on the one part and the workmen as represented by Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh of the other part, the parties agreed to refer certain disputes to my arbitration including the case of Inderpal. The said Arbitration Agreement has been published in the Gazette of India, Part II, Sec. 3(1) dated 20th February, 1965 at pages 733 to 735.

2. The terms of reference are:

- (i) Whether the action of the Management of Nowrozabad Colliery of Messrs Associated Cement Companies Limited in retiring Shri Inderpal, son of Shri Matadin, with effect from 30th September, 1963 was wrongful? and
- (ii) If so, to what relief is the workman entitled?

3. After the hearing of the matter had progressed before me the parties came to terms. The terms of the settlement are embodied in the Agreement which is hereto annexed, and which has been signed by the parties.

4. The terms of the settlement are:

- (i) The Union agrees that the retirement of Shri Inderpal, son of Shri Matadin, with effect from 30th September 1963 on his attaining the age of superannuation i.e. sixty years, as per the Company's recognised practice, is perfectly valid and fully justified;
 - (ii) The Company agrees to pay Shri Inderpal the basic wage for five months calculated at the rate of the last basic wage drawn by him at the time of his retirement on the basis of the Award of the C.G.I.T., Bombay, in reference No. 1 of 1960; and
 - (iii) The Company further agrees that as a very special case and without forming any precedent Shri Inderpal will be paid an *ex-gratia* amount of Rs. 350 (Rupees three hundred and fifty only).
5. The parties have asked me as Arbitrator to pass an Award in terms of the aforesaid settlement which is dated New Delhi 4th March, 1970.
6. The original of the terms of settlement as signed by the parties is annexed hereto and shall form part of this award.
7. I, therefore, make this award in New Delhi in terms of the said Settlement. Dated at New Delhi, this the 1st May; 1970.

Sd./- F. JEEJEEBHOY,
Arbitrator.

BEFORE SHRI F. JEEJEEBHOY, ARBITRATOR AT DELHI

In the matter of Arbitration Agreement dated 28th January, 1965 under Section 10A of the Industrial Disputes Act, regarding the retirement of Shri Inderpal s/o Matadin.

BETWEEN

The Associated Cement Companies Ltd.,
Nowrozabad Colliery,
P.O. Nowrozabad, M.P.

AND

Its Workmen,
as represented by Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh,
P.O. Nowrozabad, M.P.

MAY IT PLEASE THE HON'BLE ARBITRATOR

The parties above named beg to submit that they have come to the following settlement with regard to the above reference made to your Honour under Section 10A of the Industrial Disputes Act:

2. Terms of Reference:

- (1) Whether the action of the management of Nowrozabad Colliery of Messrs Associated Cement Cos. Ltd. in retiring Shri Inderpal s/o Matadin with effect from 30th September 1963 was wrongful?
- (2) If so, to what relief is the Workman entitled

Terms of Settlement:

- (1) The Union agrees that the retirement of Shri Inderpal s/o Matadin with effect from 30th September, 1963 on his attaining the age of Superannuation i.e. 60 years as per the Company's recognised practise, is perfectly valid and fully justified.
- (2) The Company agrees to pay to Shri Inderpal basic wages for five months calculated at the rate of last basic wage drawn by him at the time of his retirement on the basis of the Award of CGIT Bombay in Reference No. 1 of 1960.
- (3) The Company further agrees that as a very special case and without forming any precedent Shri Inderpal will be paid an *ex-gratia* amount of Rs. 350/- (Rupees Three hundred and fifty only).

3. The parties therefore, pray that the Hon'ble Arbitrator may be pleased to pass an Award in terms of the Aforesaid settlement.

Dated at New Delhi, this the 4th day of March, 1970.

For the workman:

Sd./- K. B. CHOUGULE
General Secretary,
Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh,
Nowrozabad.

for the Associated Cement
Company Limited,
Nowrozabad Colliery.

Sd./- M. S. KAPOOR,
Personnel Officer
The Associated Cement Cos. Ltd..

A formal award will be made
in terms of aforesaid.

Sd./- JEEJEEBHoy,
5/3/70.

Witnesses:

1. Sd/- N. N. SHARMA,
Personnel & Welfare Officer,
Nowrozabad Colliery,
Nowrozabad.
2. Sd/- G. R. SWAMY,
Secretary,
Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh,
Nowrozabad.

[No. 5/1/64-LR.II(II).]

S.O. 203.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri F. Jeejeebhoy, Barrister-At-Law, Advocate of the Supreme Court and arbitrator, care of Mercantile Bank Limited, Connaught Place, New Delhi-1, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Associated Cement Companies Limited, Nowrozabad Colliery, Post Office Nowrozabad, District Shahdol, Madhya Pradesh and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th May, 1970.

ARBITRATION AWARD

In the matter of Associated Cement Company Limited, Nowrozabad Colliery.

AND

Their workmen represented by the Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh.

PRESENT:

Mr. F. Jeejeebhoy, Barrister-at-law, Arbitrator.

For the employers.—Mr. I. M. Nanavati, Advocate, and Mr. M. S. Kapur, Personnel Officer.

For the workmen.—Mr. K. B. Chougule, General Secretary, Mr. Hukam Chand Gureja, President and Mr. G. R. Swamy, Secretary, Nowrozabad Colliery, Mazdoor Sangh, Nowrozabad.

AWARD: In the matter of Shri Lurka Dass.

By their Agreement dated 28th January, 1965 under Section 10A of the Industrial Disputes Act 1947 between the Associated Cement Companies Ltd. Nowrozabad Colliery on the one part and the workmen as represented by Nowrozabad Colliery Mazdoor Sangh of the other part, the parties agreed to refer certain disputes to my Arbitration including the complaint of Shri Lurka Dass under Section 33A of the I.D. Act. The said Arbitration Agreement has been published in the Gazette of India Part II, Sec. 3(II) dated 20th February 1965 at pages 733 to 735.

2. The Complaint under Sec. 33A was originally filed by Shri Lurka Dass Before the Central Government Industrial Tribunal Bombay and was numbered

as Complaint No. CGIT 3 of 1963. Later by the Arbitration Agreement dated 28th January, 1965 the said complaint, along with several other matters was withdrawn and referred to my Arbitration.

3. At the hearing on 4th March, 1970 at Delhi, both the parties stated that subsequent to the filing of the present complaint under Sec. 33A, a reference was made by an Arbitration Agreement dated 31st December 1966 referring the substantive dispute of the dismissal of Shri Lurka Dass to the Arbitration of Shri N. H. Bhagvati. By his Award dated 24th July 1967 the substantive dispute has been decided in favour of the Company, and the dismissal of Shri Lurka Dass has been confirmed. In view of the Award on the substantive issue, the complaint under Sec. 33A does not survive before me.

4. Now therefore I make my Award accordingly.

Dated at New Delhi this the 1st day of May, 1970.

Sd./- F. JEEJEEBHROY,
Arbitrator.

ORDER

New Delhi, the 22nd May 1970

S.O. 2032.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Associated Cement Companies Limited., Madukkarai and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru S. Swamikkannu, as Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal,

SCHEDULE

Whether Messrs Associated Cement Companies Limited, Madukkarai are justified in designating Shri V. Vital Das in charge of the magazine and Shri K. Velu working in the time office as Tally Checkers and paying them the wages recommended for Tally Checkers only by the Cement Wage Board? If not, what should be their designation and under what grade of pay should they be fixed?

[No. 12(14)/70-LR-IV.]

P. C. MISRA, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 22nd May 1970

S.O. 2033.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Naresh Nath Mookerjee, 8/1, London Street, Calcutta-17 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1968.

[No. 8/30/69/PF. II.]

अन, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(अन और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1970

का० प्रा० 2033.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नरेश नाथ मुकुर्जी, 8/1 लाउडन स्ट्रीट, कलकत्ता-17, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1968 के दिसम्बर के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8/30/69-नि० एक० 2]

S.O. 2034.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gladwyn Engineering Company, 13-A, Bombay Co-operative Industrial Estate, Ghatkopar, Bombay-77 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1969.

[No. 8/21/70/PF. II.]

का० प्रा० 2034.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ग्लाडवाइन इंजीनियरिंग कम्पनी, 13-ए, मुम्बई कांक्रिपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, घाट कोपर, मुम्बई-77 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1969 के दिसम्बर के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8/21/70-भ० नि० 2]

S.O. 3035.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. B. Trading Company, 9/5, Munshiganj Road, Calcutta-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment with effect from the 31st May, 1970.

[No. 8/28/70/PF. II.]

का० प्रा० 2035.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० बी० ट्रेडिंग कम्पनी, 9/5, मुन्शी गंज रोड, कलकत्ता-23 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा इकतीस मई, 1970 से लागू करती है ।

[नं० 8/28/70-म० नि० 2]

S.O. 2036.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manometer (India) Private Limited, Harischand Textile Mills Compound, Agra Road, Vikhroli, Bombay-79 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1968.

[No. 8/37/69/PF. II(i).]

का० प्रा० 2036.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैनोमीटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड; हरिश्चन्द टैक्सटाइल मिल कम्पाउंड, आगरा रोड, विखरोली, मुम्बई-70 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिनियम 1968 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[नं० 8/37/69-म० नि० 2(i)]

S.O. 2037.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies that, with effect from the 1st July, 1968 section 6 of the said Act shall in its application to Messrs Manometer (India) Private Limited, Harischand Textile Mills Compound, Agra Road, Vikhroli, Bombay-79, be subject to the modification that for the words "six and a quarter per cent", the words "eight per cent" were substituted.

[No. 8/37/69-PF. II(ii).]

का० प्रा० 2037.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रथम जुलाई, 1968 से मैसर्स मैनोमीटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड हरिश्चन्द टैक्सटाइल मिल कम्पाउंड आगरा रोड, विखरोली, मुम्बई-70 को लागू होने के सम्बन्ध में इस उपांतरण के अन्वये होगी कि "सषा छः रतिगत" शब्दों के स्थान पर "आठ प्रतिशत" प्रतिस्थापित किए जाएं ।

[नं० 8/37/69-म० नि० 2(ii)]

S.O. 2038.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Machino Enterprises, Mon Repos, Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1968.

[No. 8/23/70/PF. II(i).]

का० आ० 2038.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्डियन मशीनों एन्टरप्राइज, मान रेपास, आर्थर बन्दर रोड कोलाबा, मुम्बई-5 नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1968 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/23/70-भ० नि० 2 (i)]

S.O. 2039.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies that, with effect from the 1st July, 1968 section 6 of the said Act shall in its application to Messrs Indian Machino Enterprise, Mon Repos, Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5, be subject to the modification that for the words "six and a quarter per cent", the words "eight per cent" were substituted.

[No. 8/23/70-PF. II(ii).]

का० आ० 2039:—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रथम जुलाई 1968 से मैसर्स इन्डियन मशीनों एन्टरप्राइज, मान रेपास आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा मुम्बई-5 को लागू होने के सम्बन्ध में इस उपांतरण के अध्वययीन होगी कि "सवा छह प्रतिशत" शब्दों के स्थान के पर "आठ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं० 8/23/70-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2040.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Suresh Malhani and Company, J. C. Road, Bangalore-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1969.

[No. 8/61/70-PF. II.]

का० प्रा० 2040.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुरेश मल्हानी एण्ड कम्पनी, जे० सी० रोड, बैंगलूर-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के नवम्बर के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/61/70-पी० एफ० 2]

S.O. 2041.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kanoria Overseas Corporation, 81/83, Stadium House, Block No. 2, Veer Nariman Road, Bombay-20 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1969.

[No. 8/17/70/PF. II (1).]

का० प्रा० 2041.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वनोदिया ओवरसीज कारपोरेशन, 81/83, स्टेडियम हाउस, ब्लॉक सं० 2, वीर नारीमन रोड, मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/17/70 भ० नि० 2 (i)]

S.O. 2042.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies that, with effect from the 1st August, 1969 section 6 of the said Act shall in its application to Messrs Kanoria Overseas Corporation, 81/83, Stadium House, Block No. 2, Veer Nariman Road, Bombay-20 be subject to the modification that for the words "six and a quarter per cent", the words "eight per cent" were substituted.

[No. 8/17/70-PF. II (1)].

का० प्रा० 2042.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रथम अगस्त, 1969 से मैसर्स कनोडिया ओवरसीज कारपोरेशन, 81/83, स्टेडियम हाउस, ब्लॉक सं० 2, वीर नारीमन रोड, मुम्बई-20 को लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण के अन्वये कि "सवा छह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आठ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें।

[सं० 8/17/70-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 2043.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madras Publicity Services, A.V.M. Studios Compound, Arcot Road, Madras-26 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment with effect from the 31st May, 1970.

[No. 8/31/70/PF. II (i).]

का० प्रा० 2043.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मद्रास पब्लिसिटी सर्विसेस, ए०वी०एम० स्टूडियोज कम्पाउण्ड, आर्कोट रोड, मद्रास-26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा इकत्तीस मई, 1970 से लागू करती है।

[सं० 8/31/70-भ०नि० 2(i)]

S.O. 2044.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies that, with effect from the 31st May, 1970 section 6 of the said Act shall in its application to Messrs Madras Publicity Services, A.V.M. Studios Compound, Arcot Road, Madras-26 be subject to the modification that for the words "six and a quarter per cent", the words "eight per cent" were substituted.

[No. 8/31/70-PF II (ii).]

का० प्रा० 2044.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 इकत्तीस मई, 1970 से मेसर्स मद्रास पब्लिसिटी सर्विसेस, ए०वी०एम० स्टूडियोज कम्पाउण्ड, आर्कोट रोड, मद्रास-26 को लागू होने के तत्पश्चात् इस उपांतरण के अधीन होगी कि "सिवा छह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आठ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें।

[सं० 8/31/70-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2045.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Reeves (Artists Materials) Limited, Thana West, 1st Pokharan Road, Thana have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1969.

[No. 8/85/69/PF. II (i).]

का० प्रा० 2045.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रीव्स (आर्टिस्ट्स मटेरियल्स) लिमिटेड, थाना वेस्ट, 1 पोखरान रोड, थाना नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के अप्रैल के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/85/69-भ० नि० 2) (i)]

S.O. 2046.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies that, with effect from the 30th April, 1969 section 6 of the said Act shall in its application to Messrs Reeves (Artists Materials) Limited, Thana West, 1st Pokharan Road, Thana be subject to the modification that for the words "six and a quarter per cent", the words "eight per cent" were substituted.

[No. 8/85/69-PF. II (11).]

का० प्र० 2046.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 तीस अप्रैल, 1969 से मैसर्स रीवेज (आर्टिस्ट्स मैटीरियल) लिमिटेड, थाना वेस्ट, 1 पोखरान रोड, थाना को लागू होने के संबंध में इस उपांतरण के अन्वयधीन होगी कि "सवा छह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आठ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें।

[सं० 8/85/69-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 2047.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A.V.M. Sons, A.V.M. Studios Premises, Vadapalani, Madras-26 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment with effect from the 31st May, 1970.

[No. 8/46/70/PF. II (1).]

का० प्र० 2047.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० वी० एम० सन्स, ए० वी० एम० स्टूडियोज परिसर, वाडापालनी, मद्रास-26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा इकत्तीस मई, 1970 से लागू करती है।

[सं० 8/46/70-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2048.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies that, with effect from the 31st May, 1970 section 6 of the said Act shall in its application to Messrs A.V.M. Sons, A.V.M. Studios Premises, Vadapalni, Madras-26 be subject to the modification that for the words "six and a quarter per cent", the words "eight per cent" were substituted.

[No. 8/46/70-PF. II (11).]

का० प्रा० 2048.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 इक्कीस मई, 1970 से मैसेर्स ए० बी० एम० सन्स, ए० बी० एम० स्टूडियोस परिसर, बाडापालनी, मद्रास-26 को लागू होने के सम्बन्ध में इस उपांतरण के अध्वधीन होगी कि “सवा छह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “आठ प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाय ।

[सं० 8/46/70-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2049.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bengal Paper Trading Company, 21, Synagogue Street, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1969.

[No. 8/19/70/PF. II.]

का० प्रा० 2049.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेर्स बंगाल पेपर ट्रेडिंग कम्पनी, 21 सिनागांग स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1969 को जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी) ।

[सं० 8/19/70-पी० एफ० 2]

S.O. 2050.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Krishna Talkies, Siddhnath Road, Baroda have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1968.

[No. 8/67/70/PF. II.]

का० प्रा० 2050.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेर्स कृष्ण टाकीज, सिद्धनाथ रोड, बड़ौदा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1968 के सितम्बर के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8/67/70-पी० एफ० 2]

S.O. 2051.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yesbee Garage, 175-B, Arcot Road, Vadapalani, Madras-26 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1968.

[No. 8/51/70/PF. II.]

का० प्रा० 2051.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स यस्बी गैरेज, 175-बी०, आर्कोट रोड, वाडापालनी, मद्रास-26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1968 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8/51/70-पी० एफ० 2]

S.O. 2052.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mathur Aviation, Mon Repos, Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1968.

[No. 8/22/70/PF. II (1).]

का० प्रा० 2052.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स माथुर एवियेशन, मान रेपास, आर्थर, बन्दर रोड, कोलाबा, मुम्बई-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजन मान रेपास, आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा, मुम्बई-5 नामक स्थापन से स्थापन से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1968 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8/22/70-भा० नि० 2(i)]

S.O. 2053.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies that, with effect from the 1st July, 1968 section 6 of the said Act shall in its application to Messrs Mathur Aviation, Mon Repos, Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5 be subject to the modification that for the words "six and a quarter per cent", the words "eight per cent" were substituted.

[No. 8/22/70-PF. II (II).J

का० आ० 2053.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रथम जुलाई, 1968 से मैसर्स मथुर एविएशन, मानरेपोस आर्थर बन्दर रोड कोलाबा, मुम्बई-5 को लागू होने के सम्बन्ध में इस उपांतरण के आध्यक्षीत होगी कि "सवा छह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आठ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किया जाय।

[सं 8/22/70-पी० एफ० 2 (ii)]

New Delhi, the 26th May 1970

S.O. 2054.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1362 dated the 3rd April, 1969, the Central Government hereby appoints Shri G. H. Doari as Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the State of Orissa to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties vice Shri S. S. Chatterjee.

[No. 17/14/68-PF. I-(1).J

नई दिल्ली, 26 मई 1970

का० आ० 2054.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5B की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1362 तारीख 3 अप्रैल, 1969 को अधिकांश करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जी० एच० दोआरी को, केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त की उसके कर्तव्य के निर्वाहन में सहायता करने के लिए, श्री एस० एस० चटर्जी के स्थान पर सारे उड़ीसा राज्य के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त नियुक्त करती है।

[सं० 17/14/68-प० एफ०-1(i)]

S.O. 2055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1363 dated the 3rd April, 1969, the Central Government hereby appoints Shri G. H. Doari to be an Inspector for the whole of the State of Orissa vice Shri S. S. Chatterjee, for the purpose of the said Act and of any scheme framed thereunder, in relation of any establishment belonging to, or under the control of the Central Government, or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil field, or a controlled industry.

[No. 17/14/68-PF. I (II).J

का० आ० 2055.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं०

का० आ० 1363, तारीख 3 अप्रैल, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जी० एच० दोभ्राड़ी को श्री एस० एस० चटर्जी के स्थान पर, उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रण में स्थापन के बारे में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित स्थापन के बारे में सारे उड़ीसा राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० 17/14/68-पी० एफ० 1(ii)]

New Delhi, the 28th May 1970

S.O. 2056.—In pursuance of clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints Sarvashri V. N. Soral and M. L. Rath, as members of the Regional Committee for the State of Rajasthan, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 3140 dated the 29th August, 1967, namely:—

In the said notification,—

(a) against serial No. 4, for the entry "Shri M. L. Bhartia, Mill Secretary, Udaipur Cotton Mills, Udaipur", the following shall be substituted, namely:—

"Shri V. N. Soral, Manager, Podar Spinning Mills, Jaipur";

(b) against serial No. 5, for the entry "Shri A. C. Dev, Messrs. Jaipur Metals and Electricals Limited, Near Railway Station, Jaipur." the following shall be substituted, namely:—

"Shri M. L. Rath, M/S Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur (Western Railway)".

[No. 12(8)67-PF.II.]

नई दिल्ली, 28 मई, 1970

का० आ० 2056.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सर्वश्री बी० एन० सोरल और एम० एल० राठी को राजस्थान राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति के सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3140 तारीख 29 अगस्त, 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) क्रम सं० 4 के सामने प्रविष्टि "श्री एम० एल० भरतिया, मिल सचिव, उदयपुर कोटन मिल्स, उदयपुर" के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—
"श्री बी० एन० सोरल,
प्रबन्धक, पोदार स्पिनिंग मिल्स,
उदयपुर " ;

(ख) क्रम सं० 5 के सामने प्रविष्टि "श्री ए० सी० देव, मैसर्स जयपुर मटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रेलवे स्टेशन के निकट, जयपुर" के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

"श्री एम० एल० राठी, मैसर्स जयपुर उद्योग
लिमिटेड, सवाई माधोपुर (पश्चिमी रेलवे) "

[सं० 12(8) 67-पी० एफ० 2]

S.O. 2057.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Labour and Employment No. 1567 dated the 20th May, 1966, the Central Government hereby appoints the following officers to be Inspectors for the purposes of the Coal Mines Provident Fund Scheme, Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, Coal Mines Bonus Scheme, Andhra Pradesh Coal Mines Bonus Scheme, Rajasthan Coal Mines Bonus Scheme and Assam Coal Mines Bonus Scheme and directs that they shall, in relation to coal mines, exercise the powers and perform the functions of Inspectors under the said Act, in the States of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan, Assam, Nagaland and Tamil Nadu, namely:—

1. Shri P. D. Galha	}	Coal Mines Provident Fund Commissioner.
2. Shri R. Kumar		Deputy Commissioner, Coal Mines Provident Fund.
3. Shri S. A. Moiz	}	Regional Commissioners, Coal Mines Provident Fund.
4. Shri O. P. Sharma		
5. Shri S. P. Sharma		
6. Shri B. K. Sinha	}	Assistant Commissioners, Coal Mines Provident Fund.
7. Shri R. K. Verma		
8. Shri A. B. Prasad		
9. Shri G. C. Saren		
10. Shri N. G. Nandi	}	Assistant Commissioner (Accounts), Coal Mines Provident Fund.
11. Shri N. C. Bhattacharjee		}
12. Shri L. P. Sinha.		
13. Shri Laxmi Chandar		
14. Shri B. R. Uppal		
15. Shri P. N. Kacker		
16. Shri K. M. Burman		
17. Shri P. K. Bhattacharjee		
18. Shri S. K. Saxena		
19. Shri O. P. Agarwal		
20. Shri M. K. Sinha		
21. Shri R. K. Rajbanshi		
22. Shri M. M. Kundu		
23. Shri G. R. Bharti		
24. Shri P. N. Singh		
25. Shri G. S. Das		
26. Shri K. B. Bahl		
27. Shri Lakhan Prasad.		

Coal Mines Provident Fund Inspectors.

[No. 2(350)83-PF-I.]

का० प्रा० 2057.—कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (194 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और रोजगार विभाग की अधिसूचना सं० 1567 तारीख 20 मई, 1966 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, नेवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, कोयला खान बोनस स्कीम, आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस स्कीम, राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम और असम कोयला खान बोनस स्कीम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है और निवेश देती है कि वे, कोयला खानों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड और तमिलनाडु राज्यों में, उक्त अधिनियम के अधीन निरीक्षकों की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे, अर्थात्:—

1. श्री पी० डी० गैहा

कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त ।

2. श्री आर० कुमार

उपायुक्त, कोयला खान भविष्य निधि ।

3. श्री एस० ए० माहंज	}	क्षेत्रीय प्रायुक्त, कोयला खान भविष्य निधि ।
4. श्री जे० पी० शर्मा		
5. श्री एस० पी० शर्मा		
6. श्री बी० के० सिन्हा	}	सहायक प्रायुक्त, कोयला खान भविष्य निधि ।
7. श्री आर० के० वर्मा		
8. श्री ए० बी० प्रसाद		
9. श्री जी० सी० सरेन		
10. श्री एन० जी० नन्दी	}	सहायक प्रायुक्त (लेखा), कोयला खान भविष्य निधि ।
11. श्री एन० सी० भट्टाचार्य		
12. श्री एल० पी० सिन्हा	}	कोयला खान भविष्य निधि निरीक्षक ।
13. श्री लक्ष्मी चन्द्र		
14. श्री बी० आर० उप्पल		
15. श्री पी० एन० कक्कड़		
16. श्री के० एम० बर्मन		
17. श्री पी० के० भट्टाचार्य		
18. श्री एस० के० सक्सेना		
19. श्री ओ० गी० अग्रवाल		
20. श्री एम० के० सिन्हा		
21. श्री आर० के० राजबन्शी		
22. श्री एम० एम० कुन्दू		
23. श्री जी० आर० भारती		
24. श्री पी० एन० सिंह		
25. श्री जी० एस० दास		
26. श्री के० बी० बहल		
27. श्री लखन प्रसाद		

[सं० 2(350)/63-पी० एफ० (1)]

S.O. 2058.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 127, dated the 5th January, 1970 published in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India dated the 10th January, 1970 namely:—

For the words and figures "30th November, 1969," the words and figures "31st January, 1970" shall be substituted.

[No. 8/124/69-PF.II.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

का० प्रा० 2058.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र तारीख 10 जनवरी, 1970 के भाग 2, खंड 3 (II) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम;

रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की तारीख 5 जनवरी, 1970 की अधिसूचना सं० का० भा० 127 में, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

“30 नवम्बर, 1969” शब्दों और अंकों के स्थान पर

“31 जनवरी, 1970” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 8/124/69-पी० एफ० 2]

दलजीत सिंह,

प्रवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 23rd May 1970

S.O. 2059.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Cochin Dock Labour Board, Cochin and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th May, 1970.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
BOMBAY**

REFERENCE No. CGIT-10 of 1968

PARTIES:

Employers in relation to the Cochin Dock Labour Board, Cochin.

AND

Their workmen

PRESENT:

Shri A. T. Zambre, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the employers.—Shri P. K. Kurian, Barrister-at-Law of Messrs. Menon and Pal, Advocates, Ernakulam.

For the workmen.—Shri T. C. N. Menon, Advocate.

STATE: Kerala.

INDUSTRY: Major ports and Docks.

Bombay, dated 30th April 1970

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment by their Order No. 28(48)/67-LR/III dated 2nd June 1967 had referred to the Industrial Tribunal, Kozhikode and industrial dispute existing between the employers in relation to the Cochin Dock Labour Board Cochin and their workmen in respect of the matters specified in the following schedule:—

SCHEDULE

Whether the employers in relation to the Cochin Dock Labour Board are justified in refusing employment to the following workmen, namely:—

1. Shri Vareechan Achambi—Wage No. 695(WD).
2. Shri T. V. Kochappan—Wage No. 33-T.
3. Shri K. P. Thomas—Wage No. 33-C.
4. Shri K. Pappachan—Wage No. 561(WD).
5. Shri Ouseph Pappu—Wage No. 101 F.

If so, to what relief are the said workmen entitled?

(2) Whether demand of the workmen who were on strike from the midnight of the 30th November/1st December 1966 to 8th December 1966, for grant of

continuity of service and wages from the 9th December, 1966 to the date of their reinstatement (both days inclusive) is justified? If so, to what relief are they entitled?

2. During the pendency of this reference Shri V. V. Subramania Iyer, the Presiding Officer of the Tribunal retired and the reference came before Shri K. K. Venu Nayar Industrial Tribunal, Kozhikode. But subsequently this reference was withdrawn along with other cases and was transferred to this Tribunal for adjudication with a direction to proceed with the disputes *de novo* and dispose of the same according to law.

3. The schedule to the reference order contains two issues for decision. The first is in respect of the refusal of employment to the five workmen mentioned and the second is in respect of the demands of the workmen who were on strike for continuity of service and wages and the facts and circumstances giving rise to these disputes may be stated in brief as follows:—

4. After the constitution of the Cochin Dock Labour Board and the introduction of the Cochin Dock Workers' (Regulation of Employment) Scheme the stevedores labour working in the Cochin Port was de-casualised and the Cochin Dock Labour Board registered the workers in the pool in the year 1962 according to the provisions of the Dock Labour (Regulation of Employment) Scheme. This registration was finalised under an award of the Tribunal in I.D. No. 3/61 on 4th November, 1962. A large number of workmen who were working in the docks could not be included in the reserve pool and hence the Tribunal had directed the Board to prepare a casual list of the workmen who could not be included in the list and to give them preference for employment.

5. Before the registration of the stevedore labour there were only two unions of works at Cochin Viz., the Cochin Thuramugha Thozhilali Union C.T.T.U. and the Cochin Port Thozhilali Union C.P.T.U. There was at that time a practice prevalent where-by tokens were issued by the two unions to the workers who were to report for employment. After the registration in the reserve pool the workers were free to join or form any union and in the year 1963 a third union was formed. It was the Cochin Dock Labour Union C.D.L.U. to which both the registered and unregistered workers joined. The C.T.T.U. and the C.P.T.U. were recognized unions and were represented on the Dock Labour Board. The Cochin Dock Labour Union was not recognized and was not represented on the Board.

6. Though the Tribunal had given a direction in the award for the preparation of a casual list of the workmen who could not be included in the reserve pool for giving them preference no such list was prepared and the Board used to employ the casuals as before and hence there arose disputes. On account of the non-recognition of the C.D.L.U. its member could not get the employment of casual workers and there was discontent.

7. The workmen in this reference are the members of the Cochin Dock Labour Union which has by its statement of claim contended that till 4th November, 1962 the C.P.T.U. and the C.T.T.U. were given the exclusive right to supply labour for stevedoring work in the port of Cochin; and though this union had a membership of 900 workers both registered and unregistered from its very inception the officials and members of the Board were taking a hostile attitude towards the members of this union. The Board did not prepare the list of casual workers and began to recruit extra workers through the C.T.T.U. and the C.P.T.U. The members of this union were not also given employment in casual vacancies and instead the Board used to employ fresh recruits through the two unions in casual vacancies. A large number of reserve pool workmen were also punished in the year 1965 and 1966 but the Board authorities did not consider the representations made by this union and in view of the attitude of the Board the union served a strike notice detailing the grievances of its members on 30th October 1966 and specified the demand by another letter dated 8th November 1966.

8. But the Board did not give any reply to the union about the strike notice. On 30th November 1966 the Assistant Labour Commissioner (Central) had called a conciliation conference in which this union expressed their willingness to refer the dispute for arbitration in order to avoid a strike but the representatives of the Board flatly refused this offer. The union has alleged that this was done deliberately to precipitate a strike and then to victimise its members. And hence the members of the union went on strike from 1 A.M. on 1st December 1966, which strike was called off at the intervention of the Port Dock and Waterfront Workers' Federation, the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi and the Joint Secretary to the Ministry of Labour New Delhi who assured that the Chief Labour Commissioner would visit Cochin before the end of December and enquire into the grievances of the workmen.

9. The strike was called off from 9th December 1966, by a letter handed over to the Board on the previous day. On the 9th December all the workmen who were on strike reported for duty to the Board but all of them were refused employment. They were not told any reason for refusal of employment. In the meantime the Labour Officer of the Board had issued notices to 257 workers who were on strike and who had commenced the strike at 1 A.M. on 1st December 1966 directing them to explain why action should not be taken against them and those workmen submitted their explanations. Similarly the workmen who were refused employment on 9th December, 1966 also submitted many representations to the Board stating that they were on strike and they should be taken back but no reply was given to any of them.

10. It is contended that after 9th December 1966 the C.P.T.U. and the C.T.T.U. began to coerce the workers to resign from the membership of this union and submit apologies to the Board for having gone on strike. The Board also connived with the two unions and reinstated only those workers who had submitted to the direction of the two unions. It is alleged that the Board did not either send any notice or any intimation to the workers informing them about their service. They did not also put up any notice stating that the workmen would not be given employment. Ultimately because of the sustained agitation and intervention of the Central Government the Board agreed before the Hon'ble High Court in Writ Application No. 59/67 that the workers who were found to have gone on strike from 1st December 1966 to 8th December 1966 would be permitted to join duty. But in spite of the same the Board did not take into employment the five workers who were on strike, and even in respect of the workers who were taken back in service, they were deprived of their past services and wages and hence this reference.

11. The Cochin Dock Labour Board by its written statement denied the allegations made by the union and has contended that before the registration of the casual Labour for a long time there were only two unions of the workers in the Cochin Port viz. The Cochin Port Thorumugha Thozhilali Union and the Cochin Port Thozhilali Union, and the workers were the members of either of these two unions. There was no question of any right being given to the unions to supply any labour and the practice regarding tokens to be shown by the workmen for casual employment was only for the purpose of knowing that these worker was one who was getting employment in the docks before. The Board has not admitted that about 900 workers were members of the Cochin Dock Labour Union. Regarding replies to the letter Board stated that it was not a recognised union and therefore the Board was not in correspondence with that union, and there was no question of any hostile attitude being taken up by the Board towards the union. Regarding the delay in the preparation of the casual labour list it is alleged that the delay was caused by the Cochin Dock Labour Union itself by filing a writ petition against the award in I.D. No 3 of 1961 and the finalisation of the list had to be done after the writ petition was disposed of. The extra workers required are being recruited through the normal channels and it was not correct to say that they were taken through the Cochin Thuramugh Thozhilali Union or the Cochin Port Thozhilali Union, and nothing was done by these two unions to compel the members of the Cochin Dock Labour Union to resign from that union.

12. The Board has admitted that the union had sent them the strike notice dated 30th October 1966, and the letter dated 8th November 1966 mentioning the demands which showed that the strike was to commence on 1st December 1966. They submitted that according to the notice and this letter the workmen could go on strike only from the morning shift of 1st December 1966 but certain workmen left their work spot without permission after midnight on 30th November 1966. This was considered to be a misconduct under standing order 19(b)(34) and accordingly they were chargesheeted for the misconduct. As regards the remaining workers they were absenting without leave from 1st December 1966 onwards. This situation was considered by the Board at its meeting held on 8th December 1966 and it was decided that those who have been absenting themselves will be considered as having left the services of the Board voluntarily as per clause 18 of the standing Orders.

13. It is alleged that this decision of the Board was known to the workmen and it was for them to act under the provisions of the standing order by submitting the necessary explanations to the satisfaction of the Administrative Body or the Dock Labour Board. Those who reported for duty and submitted satisfactory explanations were allowed to join duty. The Board has denied the contentions that the workers who were on strike reported for work on 9th December 1966. It is contended that though the union wrote to the Board on the evening of 8th December 1966 that the strike was called off a number of persons who were on strike did not report for work on 9th December 1966 or thereafter.

Individual workmen who had submitted satisfactory explanations were considered and were allowed to join duty and there was no question of victimization.

14. The Board has admitted the receipt of the joint application of the workmen but have contended that it was received on 31st December 1966 and on scrutiny it was found that it was not possible to treat the joint application as genuine. People who were on leave during the relevant period and who had joined duty before then had purported to give the explanation that they were on strike. There were many such factual mistakes and with all these inaccuracies and duplications the total number included in that list was 512 and it was thought that it would not be safe to act on such a mass petition and no action could be taken.

15. It has been further contended that from the 17th January 1967 onwards a number of letters were received from the 1st December 1966, and these explanations were to be considered by the Board and by the time steps were taken orders were received from the Hon'ble High Court prohibiting the Board and administrative body from acting upon the resolution and the consideration of the explanations was deferred. The original petition of the union was disposed of by the Hon'ble High Court by its judgment dated 6th March 1967 and thereafter steps were being taken for considering the explanations and there was no question of the Board denying employment to any of the workers. The workers did not report for work nor did they submit the necessary explanation as required under standing order 18 at the appropriate time, and as and when such explanations were given and they reported for work they were allowed to join duty when it was found that the explanations were satisfactory.

16. As regards the five workmen mentioned in the reference order the Board has denied the allegations about victimisation. The averments made by them were incorrect. The workmen were fully aware of the circumstances and there was no violation of the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme and they were not entitled to be reinstated with or without back wages. As regards the other workers it is contended that the Board never intended to refuse employment to the workers who went on strike. There was no intention to weaken the union or victimize the workers, who were the members of the union. The workers concerned should have submitted their explanations and as the workmen did not report for duty on 9th December 1966 or immediately thereafter they were not entitled to their wages. The action of the Board was not illegal nor without any authority nor had the Board acted *mala fide* or in contravention of the provision of the scheme and the workers were not entitled to claim any relief.

17. After the statement of claim the written statement and rejoinder both parties filed a number of documents and list of witnesses. The union examined its president and three witnesses and the Dock Labour Board also examined its three witnesses. Though the union had cited the chairman of the Board as one witness in their list the Dock Labour Board did not examine the chairman as the witness of the Board though he had signed the written statement. On the day, the Board closed its case Shri T. C. N. Menon the President of the Union submitted an application for the examination of the Chairman of the Board as witness in case. He has contended that the Deputy Chairman of the Board when he was examined was not able to give evidence on many important matters relevant to the issue referred and it was therefore necessary that the Chairman of the Board should be examined as a witness in order that the whole action of the Board relevant to the issues should be brought on record. It was further contended that the written statement of the Board was signed by chairman and in the interest of justice the Chairman of the Board should be summoned to appear and give evidence.

18. The Board had seriously opposed the application firstly contending that it was not supported by an affidavit and secondly that the relevant evidence necessary for the union to establish its case should be obtained by examination of their witnesses and it was not a ground for justifying the examination of the Chairman of the Board. It was further contended that the practice of summoning the opponent as witness was objectionable and should never be permitted and the application should be dismissed.

19. But before the decision of this application the Dock Labour Board sent a petition raising preliminary objections to the reference on the ground of jurisdiction of the Tribunal. It was alleged that the Dock Labour Board was not carrying on an industry and the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 were not attracted. There was no employer employee relationship between the Cochin Dock Labour Board and the workmen registered in the reserve pool. The Board was a statutory body charged with the duty of administering the

scheme and was not an industry. It was further contended that the Hon'ble Supreme Court in their decision reported in 1970 1 LLJ 46 found the position to be so with regard to the Vizagapatnam Dock Labour Board and their workmen and it was also held in that case that the Cochin Dock Labour Scheme was substantially similar to the one they were considering. The decision of the Supreme Court was published in the January issue of the Labour Law Journal and hence the Board could not make the application earlier and this issue raised should be treated as preliminary and dispose of the same before further considering the merits of the dispute including the petition filed by the union for the examination of the Chairman of the Dock Labour Board as witness in this case.

20. Notice of this application was issued to the Cochin Dock Labour Union which did not send any reply but on the date of hearing opposed the application contending that the Dock Labour Board had not taken such a plea in their written statement. They had not raised the question about employer employee and this application should not be entertained at this stage and the issue should not be treated as preliminary. It was contended that the issue raised was not merely a question of law but involved both questions of law and fact that if at all the application was entertained it should be decided along with the merits of the reference. Regarding the merits of the application it was contended that the case before their Lordships of the Supreme Court was in respect of bonus. The Labour Appellate Tribunal had in their decision in the Bombay Dock Labour Appeals held that the Dock Labour Board was the general employer and the stevedores were the particular employers and there was employer-employee relationship between the stevedore labour and the Dock Labour Board. This decision was not brought to the notice of their Lordships. Even according to the scheme the workmen were to be deemed in the employ of the Dock Labour Board. The case before their Lordships was in respect of bonus which is not applicable to the facts of this case and the application should be rejected.

21. The Dock Labour Board had closed its case after examining their witness on 10th February 1970. The union had examined their witnesses earlier at the time of the previous hearing and it is clear that the Dock Labour Board had given the application raising the new pleas at the far end of the case. It is also clear from the record and it is not in dispute that the case is very hotly contested. There are serious allegations both against the Chairman of the Dock Labour Board, and the representatives of the other two unions on the Board and ordinarily raising additional pleas at the far end of the case would not have been allowed. However the contention raised goes to the root of the case. It is also based upon the new ruling of the Supreme Court published in January of the LLJ and I think it proper to consider the plea raised as a preliminary issue and decide the same before discussing the merits of the case.

22. While stating the facts I have already mentioned the issues referred for adjudication. The Disputes is between the Dock Labour Board and the Stevedore labour who are registered pool workers and the ruling cited by the Dock Labour Board reported in 1970 LLJ 1 page 58 (Visakhapatnam Dock Labour Board and Stevedores' Association Visakhapatnam and others) will be applicable. In that judgment their Lordships have discussed the Dock Workers Regulation of Employment Act, 1948 and the provisions of the Visakhapatnam Dock Labour Scheme and have observed:—

"From the various provisions of the Act and the scheme referred to above it is evident that the Board is statutory body charged with the duty of administering the scheme the objection of which is to ensure greater regularity of employment for dock workers and to ensure that an adequate number of dock workers are available for the efficient performance of dock work. The Board is an autonomous body competent to determine and prescribe the wages and allowance and other conditions of service of the dock workers. The purport of the scheme is that the entire body of workers should be under the control and supervision of the Board. The registered employers are allocated monthly workers by the administrative body and the administrative body supplies whenever necessary the labour force to the stevedores from the reserve pool. The workmen who are allotted to the registered employers are to do the work under the control and supervision of the registered employers and to act under their directions. The registered employers are to act under their directions. The registered employers pay the wages due to the workers to the administrative body and the latter in turn as agent of the registered employer pay them over to the concerned workmen.

All these circumstances in our opinion *prima facie* establish that the board cannot be considered to be the employer of the dock labour workmen. In fact the various provisions referred to in the scheme clearly show that the registered employer to whom the labour force is allotted by the board is the employer whose work of loading or unloading of ships is done by the dock workers allotted to them."

From these observations it is clear that the Dock Labour Board is a statutory body and it cannot be considered to be the employer of the dock labour. It is not in dispute that the Cochin Dock Labour Scheme and the Visakhapatnam Dock Labour Scheme are substantially similar and in view of the observations of their Lordships it shall have to be said that there is no employer-employee relationship between the Dock Labour Board and the Workmen who are the registered pool workers and involved in this reference.

23. It is true that the Dock Labour Board has not taken such a plea in their written statement or had never denied that the workmen were their employees. It is also clear from the Dock Scheme paragraph 37(2) that the framers of the scheme have created the fiction of the relationship between the Dock Labour Board and the registered pool workers and the clause provides:—

"The registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall be deemed to be in the employment of the Board."

It is also clear from the statement of the Dock Labour Board that according to them they had taken steps against the workmen under clause 18 of the standing orders which provide for the conditions of service of the workmen. It is clear from the standing order exhibit E-4 that the standing orders have been certified under the Industrial employment standing Order Act, 1946 and it shall have to be presumed that both the parties have taken for granted that the Board was running an industry. The preamble of the Industrial Employment (Standing Orders) Act provides:—

"Whereas it is expedient to require the employers in industrial establishments to define with sufficient precision the conditions of employment under them and to make such conditions known to the workmen employed by them "From this it can be argued that there was no doubt about the question that the Board was running an industry and the labourers were workmen. However, I donot think it is open for me to discuss these questions and the submissions made. In view of the decision of the Hon'ble Supreme Court it shall have to be presumed that their Lordships have considered all these aspects and have held that there is no employer-employee relationship between the Dock Labour Board and the workers of the reserved pool. The ruling is applicable to the facts of this case. As there is no employer-employee relationship there is no dispute between employers and workmen and it shall have to be held that this is not an industrial dispute and this Tribunal has no jurisdiction.

24. It has also been held in this along ruling of the Supreme court that the Dock Labour Board was not running an industry and their Lordships have observed:—

"The matter can also be considered from another point of view viz. can it be stated that the Board is carrying on an industry so as to attract the provisions of the Industrial Disputes Act. We have already referred to the various circumstances which will show that there is no employment as such of the dock worker by the Board. As observed by this Court in *Gymkhana Club V. Management*(4). What matters is not the nexus between the employee and the product of the employer's efforts but the nature of the employer's occupation. If his work cannot be described as an industry his workmen are not industrial workmen and the disputes arising between them are not industrial disputes. The cardinal test is thus to find out whether there is an industry according to the denotation of the word in the first part. The second part will then show what will be included from the angle of employees." Dealing with the definition "industry" the Court further observed:—

"The definition of "industry" is in two parts, in its first part it means any business, trade, undertakings, manufacture or calling of employers. This part of the definition determines an industry by reference to occupation of employers in respect of certain activities. These activities are specified by five words and they determine what in 'industry' is and what the cognate expression 'industrial' is intended to convey. This is denotation of the terms or what the work denotes.

We shall presently discuss that the words business, trade undertaking, manufacture or calling comprehend. The second part views the matter from the angle of employees and is designed to include something more in what the term primarily denotes. By the second part of the definition any calling, service employment handicraft or industrial occupation or a vocation of workmen is included in the concept of industry. This part gives the extended annotation. If the activity can be described as an industry with reference to the occupation of the employers the ambit of the industry under the force of the second part takes in the different kinds of activity of the employees mentioned in the second part. But the second part standing alone cannot define 'industry' an industry is not to be found in every case of employment of service."

Dealing with the expression 'industrial dispute' in the Industrial Disputes Act this Court further proceeds to state in the above decision at page. 757:

".....The words are 'industrial dispute' and not trade dispute. Trade is only one aspect of industrial activity; business and manufacture are two others. The word also is not industry in the abstract which means diligence or assiduity in any task or effort but a branch of productive labour. This requires co-operation in some form between employers and workmen and the result is directly the product of this association but not necessarily commercial."

and wound up the discussion at page 758 thus:

"Industry is the nexus between employers and employees and it is this nexus which brings two distinct bodies together to produce a result."

"Applying the above principles to the case on hand, in our opinion, it is clear that it cannot be stated that the Board functioning under the Act and the Scheme carries on any industry so as to attract the provisions of the Industrial Disputes Act."

I have already observed that the Visakhapatnam Dock Labour Scheme and the Cochin Dock Labour Scheme are similar. There is no difference and in view of the observations and conclusions it shall have to be held that the Cochin Dock Labour Board does not carry on an industry.

It is clear from the definition of workman under section 2(s) of the Industrial Disputes Act that only persons who are employed in an industry would be workmen under the Act. In view of this finding of the Hon'ble Supreme Court the Cochin Dock Labour Board is not running an industry and consequently even if it be held that the workers are their employees they are not workmen and will not be covered by the definition under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, and there is no question of a dispute between workmen and workmen and employers and workmen and as the dispute is not an industrial dispute this Tribunal will have no jurisdiction and it shall have to be held that the reference is not maintainable. Hence my award accordingly.

No order as to costs.

A. T. ZAMBRE, Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal, Bombay.

[No. 28(48)/67-IR-III/P&D.]

C. RAMDAS, Dy. Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 25th May 1970

S. O. 2060.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948 and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation No. S. O. 2988 dated the 1st October 1955, the Central Government hereby reconstitutes the Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh consisting of the following members, namely:—

- | | |
|--|----------------|
| 1. Labour Minister, State of Andhra Pradesh, Hyderabad | Chairman. |
| 2. Collector, Nellore | Vice-Chairman. |
| 3. Chairman, Zilla Parishad, Nellore | Member. |

- | | |
|--|--|
| 4. Shri O. Venkatasubbiah, Member, Legislative Assembly, Andhra Pradesh | Member. |
| 5. Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad | Member. |
| 6. Shri P. Kota Reddy, Mica Chamber of Commerce, Gudur | Members representing the mica mine owners of Andhra Pradesh. |
| 7. Shri A. Shyama Sundara Reddy, South India Mica Mine Owners' Association, Gudur. | |
| 8. Shri P. C. Reddy, President, Andhra Pradesh Mica Labour Union, Gudur. | Members representing mica mine workers of Andhra Pradesh. |
| 9. Dr. S. Ramachandra Rao, President, Bharatiya Mazdoor Sangh, Gudur. | |
| 10. Shrimati Thota Anasuyamma, Ganganammabet, Tenali, Guntur District, Andhra Pradesh. | Woman Representative |
| 11. Secretary, Mica Mines Labour Welfare Fund, Andhra Pradesh. | Secretary. |

[No. F. 3(22)/69-M III]

C. R. NAIR,
Under Secy.

(अम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई 1970

का० आ० 2060.—अभ्रक खान अम कल्याण निधि नियम, 1946 के नियम 3 के उपनियम (2) के साथ पठित अभ्रक खान अम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2988 तारीख 1 अक्टूबर, 1966 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के लिए सलाहकार समिति को एतद्वारा पुनर्गठित करती है जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- | | |
|--|---|
| 1. अम मंत्री, आंध्र प्रदेश राज्य, हैदराबाद | अध्यक्ष |
| 2. कलक्टर, नेल्लोर | उपाध्यक्ष |
| 3. अध्यक्ष, जिला परिषद्, नेल्लोर | सदस्य |
| 4. श्री ओ० ब्रैकटासुब्बया, सदस्य, विधान सभा, आंध्र प्रदेश | सदस्य |
| 5. क्षेत्रीय अम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद | सदस्य |
| 6. श्री पी० कोटा रेड्डी, माइका चेम्बर आफ कॉमर्स, गडूर | आंध्र प्रदेश के अभ्रक खान मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य |
| 7. श्री ए० श्याम सुन्दर रेड्डी, साउथ इंडिया माइका माइन प्रोनर्स एसोसिएशन, गडूर | |
| 8. श्री पी० वी० रेड्डी, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश माइका लेबर यूनियन, गडूर | आंध्र प्रदेश के अभ्रक खान कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य |
| 9. डा० एम० रामचन्द्र राव, अध्यक्ष, भारतीय माइका मजदूर संघ, गडूर | |
| 10. श्रीमती थोटा अनासुयम्मा, गंगानम्मापेट, तेनाली, गंटूर जिला, आंध्र प्रदेश | महिला प्रतिनिधि |
| 11. सचिव, अभ्रक खान अम कल्याणनिधि, आंध्र प्रदेश | सचिव |

[सं० फ० 3(22)/69-एम 3]

सी० आर० नायर,
प्रवर सचिव ।

(Department of Labour & Employment)

New Delhi, the 30th May 1970

S.O. 2061.—Whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest to add to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), "pyrites mining" industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby adds the following item to the First Schedule to the said Act, after item 19 thereof, namely:—

"20. Pyrites Mining".

[No. F.1/21/70-LRI.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

(अस और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1970

का० प्रा० 2061—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की 14) की प्रथम अनुसूची में "पाइराइट खनन" उद्योग को जोड़ना लोकहित में समीचीन है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, उसकी मद 19 के पश्चात् एतद् द्वारा निम्नलिखित मद जोड़ती है, अर्थात्: —

"20. पाइराइट खनन"

[सं० का० 1/21/70-एल० आर० I]

एस० एस० सहस्त्रनामान, असर सचिव।